● वर्ष-5
● अंक-297
रायपुर, गुरुवार
30 जुलाई 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> धरती का श्रृंगार हैं वृक्ष...

लोकसभा में गृहमंत्री पर राहुल टिप्पणी का सत्ता पक्ष का कड़ा विरोध, हंगामे से कार्यवाही बाधित

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित

नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जंतर-मंतर पर छात्रों पर कथित गोलीबारी को लेकर दिए गए बयान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। इसके बावजूद सरकार ने विधेयक को सदन से पारित करा लिया। सरकार ने कहा कि यह संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मामले में तेजी से कार्रवाई कर चुकी है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संशोधन सरकार की उस सोच को दिखाता है, जिसमें पिछले अनुभवों से सीख लेकर कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष



2024 में एंटी पेपर लीक कानून लागू होने के बाद अब तक 52 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के कारण होने वाली आत्महत्याओं में भी कमी आई है, जिसे उन्होंने कानून के सकारात्मक प्रभाव का संकेत बताया। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों का आंदोलन गुस्सा, हिंसा या नफरत नहीं, बल्कि देश के युवाओं की भावनाओं और चिंताओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल, यहां तक कि भाजपा को भी छात्रों की बात सुननी चाहिए।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर लगेगी रोक, लोकसभा में विधेयक पेश

जन्म और मृत्यु प्रमाण बनाने की प्रक्रिया को कड़ा करने के लिए सरकार ने जन्म और मत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश किया है। गृह मंत्रालय की ओर से पेश किये विधेयक का उद्देश्य फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर अंकुश लगाना है।विधेयक में जन्म या मृत्यु के दो साल से अधिक समय बाद प्रमाण पत्र बनाने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य करने के प्रविधान है।दरअसल एसआईआर के दौरान कई राज्यों और खासकर पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जन्म प्रणाण पत्र बनाए गए थे। इनमें बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया होने की आशंका है। इसे देखते हुए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सख्त करने का फैसला किया।

लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिले इस विधेयक में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक जन्म या मृत्यु के एक साल से दो साल के बीच पंजीकरण के लिए डीएम, एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी।

अनुमति देने वाले अधिकारी को उसकी सत्यता की जांच करनी होगी। यदि जम्म या मृत्यु के दो साल बाद पंजीकरण का आवेदन आता है तो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होगी, जिसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य है।तीन साल पहले भी इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके बाद सभी राज्यों को जन्म और मृत्यु का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उसे हर महीने पर भारत के महा पंजीयक को भेजना अनिवार्य कर दिया गया था। अभी तक देरी की स्थिति में एसडीएम के आदेश से स्थानीय निकाय जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

वंदे मातरम् के अनादर को रोकने वाला विधेयक राज्यसभा से पास

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के अनादर को रोकने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। जो अब गुरुवार को लोकसभा में पेश होगा। इस विधेयक के तहत अब वंदे मातरम् को भी जन-गण-मन जैसा ही सम्मान मिलेगा।वहीं जानबूझकर इसे गाने से रोकने या बाधा डालने को अपराध माना जाएगा। जिसमें तीन साल की सजा का भी प्रविधान किया गया है। वहीं विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित उसके सहयोगी दूसरे विपक्षी दलों ने पहले तो काफी देर तक हंगामा किया, बाद में वाकआउट कर गए।

इस दौरान विधेयक पर राज्यसभा में करीब घंटे भर चर्चा हुई। जिसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजेडी की सुलता देव, शिवसेना से ज्योति नागनाथ, आरपीआइ से केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आदि ने हिस्सा लिया।

संसद में गूंजा पुलिस कार्रवाई का मुद्दा, राज्यसभा में खरगे और नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक

नई दिल्ली। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर पहले से गर्म राज्यसभा में बुधवार को सियासी पारा तब और चढ़ गया, जब शून्यकाल में सीपीआई (एम) दफ्तर में की गई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पुलिस की कार्रवाई पर



तीखी आपत्ति जताई और कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के दौर में हमने इससे भी खराब दिन देखें है। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ।राज्यसभा में यह वाकया तब हुआ, जब शून्यकाल में सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने मंगलवार को पार्टी के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और पूछा पुलिस कैसे किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर किसी को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की।

इस दौरान उनकी मांग का कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी समर्थन किया और कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में घुसकर सीबीआई लोगों को उठा रही है। देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। किसी को गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में एजेंसियां प्रवेश कर रही हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए।खरगे के आरोपों पर नड्डा ने कहा कि पुलिस ने केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की थी। मैंने तो कांग्रेस के दौर में इससे बदतर दिन देखे हैं। छात्र जीवन के दौरान मैं कई बार गिरफ्तार किया जा चुका हैं। मुझे क्लासरूम से इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है।

भाजपा अध्यक्ष किरणदेव सड़क हादसे में घायल

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। यूपी के झांसी से सटे ललितपुर में बुधवार दोपहर एनएच-44 पर उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। सामने से आ रही एक वाहन को बचाने के चक्कर में उनकी इनोवा ट्रक में जा घुसी। उनके साथ सुरक्षा प्रहरी भी थे वे भी घायल हो गए हैं।

चालक गौतम कुमार भी घायल है। परिवार के सदस्य पीछे दूसरी वाहन में थे। बताया जा रहा है कि वे बागेश्वरधाम से वापस लौट रहे थे।



घटना की सूचना पर तत्काल प्रशासन व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गए थे। तत्काल उन्हे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। कमर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोट पहुंची है ऐसा बताया जा रहा है। उन्हे हेलीकाप्टर से रायपुर लाया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद घायल दोनों लोगों को पहले सीएससी तालबेहट में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

इस एक्सीडेंट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कमर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। फिलहाल, उनका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि झांसी-ललितपुर मार्ग पर सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई।



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम पंडरीपानी स्थित कैलाशपति धाम मनकामेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान मनकामेश्वर महादेव के दर्शन कर शिवलिंग पर जल अर्पित किया तथा विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी उपस्थित थे।

एक राष्ट्र-एक चुनाव समिति को मिला और वक्त

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बिल की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति को नया सेवा विस्तार दिया गया है। अब यह समिति शीतकालीन सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकेगी। बुधवार को लोकसभा में समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय मांगा था।सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूर कर लिया। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होता है और क्रिसमस से पहले खत्म हो जाता है। कार्यकाल बढ़ने से अब समिति को इस बड़े बदलाव पर और अधिक विचार विमर्श करने का समय मिल गया है।यह 41 सदस्यों वाली समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 की बारीकी से जांच कर रही है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ढांचे को लागू करना है। सरकार की योजना साल 2029 तक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की है।

प्रमुख समाचार

पूर्व पीएम मनमोहन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है। यह फैसला कोर्ट ने एक अपील के बाद लिया है और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें



सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर उन्हें ट्रायल का सामना करने के लिए समन भेजा गया था। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने या सिंह के खिलाफ मामले का संज्ञान लेने का कोई ठोस कारण नहीं था। बेंच ने कहा, जांच एजेंसी की रिपोर्ट को स्वीकार करने के संबंध में इस कोर्ट द्वारा लगातार तय किए गए पैमानों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि संबंधित जज के पास सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज करने और संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। हम अपील को मंज़ूरी देते हैं और विवादित फैसले को रद्द करते हैं।

प्रहलाद जोशी पर हमलावर प्रियंका बोलीं- पीछे नहीं हटूँगी

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 29 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के खिलाफ अपना रुख दोहराते हुए उन आरोपों को खारिज कर दिया कि लोकसभा में उनकी टिप्पणियां असंसदीय थीं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनके बयान पुष्ट तथ्यों पर आधारित



थे और उन्होंने महिलाओं के प्रति एक खास तरह के रवैये (सिस्टमिक एटीट्यूड) की ओर इशारा किया। वाड्रा ने कहा कि संसदीय कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकियों से वह पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने पिछली घटनाओं का ज़िक्र किया, जिसमें 2009 के मैंगलोर पब हमले से जुड़े एक व्यक्ति को बीजेपी में शामिल करना भी शामिल था; उन्होंने इसके लिए प्रह्लाद जोशी को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसमें असंसदीय क्या था? यह तो बस सच था। अगर वे सच बोलने के लिए मुझे सज़ा देना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं सच ही बोलूँगी। आपने देखा है कि इसके वीडियो मौजूद हैं, और यह सिर्फ़ एक ही मामला नहीं है।

30 करोड़ गाड़ियां ई-20 पेट्रोल से होंगी कबाड़ : केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ई-20 पेट्रोल को लागू करने के लिए गुंडागर्दी का सहारा ले रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दावा किया कि इस



कदम से 2023 से पहले बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल कंपनियों को चुप रहने के लिए धमका रही है। केंद्र सरकार के इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने के कदम पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ई-20 पेट्रोल लागू करने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। कुछ दिन पहले, मैंने 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियों में ई-20 ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने यह भी पूछा था कि अगर गाड़ियां खराब हो जाती हैं या माइलेज कम हो जाता है, तो क्या वे मुआवज़ा देंगी।

आइशी घोष की गिरफ्तारी के प्रयास पर विपक्ष का हंगामा

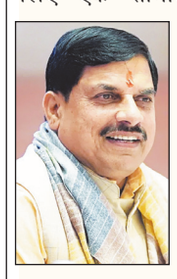
नयी दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण करीब 40 मिनट के लिए दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आइशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई।

सीएम मोहन यादव ने किसानों से बातचीत के लिए बनाई कमेटी

भोपाल। मूंग की खरीद और खेती से जुड़ी दूसरी मांगों को लेकर चल रहे किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से बातचीत करने और बातचीत के ज़रिए उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति बनाई है। सीएम यादव ने



प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील की कि वे इस बात का ध्यान रखें कि आम जनता को कोई परेशानी न हो। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य इस साल को कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर मना रहा है और सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पूरे मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं और किसानों के फ़ायदे के लिए कई काम कर रहे हैं। मैंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई है। मंगलवार को हमने राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना को भेजा था, और बुधवार को भी हमारी टीम- जिसमें कृषि मंत्री कंषाना, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री राकेश सिंह और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं- किसानों के साथ बातचीत करेगी।

संदर्भ : धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र

देश के युवाओं से संवाद की प्रक्रिया से मिलेंगे सकारात्मक परिणाम

डॉ. प्रवीण दाताराम

देश के प्रधानमत्री ने देश की अंदरूनी शान्ति के लिए या आगे किसी बड़े लक्ष्य को साधने के लिए ऐसी फॉरेन फंडेड, फॉरेन लेंग्वेज्ड, फॉरेन फीडेड, फॉरेन माइंडेड और निर्लज्ज शक्तियों के आगे समर्पण कर दिया है। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए और समय की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उनका यह कदम बड़प्पन से परिपूर्ण कदम तो है किंतु, दीर्घकालिक दृष्टि से है तो यह गलत ही। इसके परिणामों के प्रति देश को अभी से सचेत होना होगा।

छात्रशक्ति की बात रही तो सर संघचालक जी मोहन भागवत जी ने स्पष्ट परामर्श (स्वयंसेवक के लिए निर्देश) दिया है कि हमें बच्चों से संवाद बढ़ाना ही होगा। देश किशोरों, युवाओं, विद्यार्थियों से संवाद की यह प्रक्रिया अब बढ़ेगी भी और निश्चित ही सकारात्मक परिणाम भी देगी। नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि कानून वापिस लेते समय मैंने एक आलेख में लिखा था जनमत के दबाव में देश के राजा द्वारा अपने निर्णय बदलना राजा के जीवंत, विवेक, मर्म व उत्तरदायित्व भाव का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी लोकभीरु (जनता से डरने वाले) हैं तो यह शुभ-लक्षण है।

यह भी सही है कि धर्मेन्द्र प्रधान जी का त्यागपत्र कराना ही था तो लष्ट के समय ही करा लेना था। वह सही समय था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का यह समय ठीक नहीं है। आद. प्रधानमंत्री जी ने धर्मेंद्र जी प्रधान से त्यागपत्र लेकर किसी शेर की भांति एक कदम पीछे लिया है तो किसी दीर्घकालिक एजेंडे की रक्षा और पूर्ति के लिए ही किया होगा। निश्चित ही उन्होंने संघशक्ति की प्रेरणा से यह कदम राष्ट्रहित में ही उठाया होगा।

इंटरनेट पर यहाँ-वहाँ बिखरे पड़े इस आंदोलन के सैकड़ों वीडियो देखिए, फिर सोचिए। फिर अपने आसपास के छात्रों को अवश्य देखिए। अपने नगर के सैकड़ों छोटे-बड़े सभी कालेज के विद्यार्थियों का बारीकी से चुपचाप परीक्षण और अध्ययन कीजिए। इसके बाद सोचिए और बताइये कि इस वीडियो में जो हैं, क्या वे विद्यार्थी हैं? और यदि हैं भी तो क्या ऐसे विद्यार्थियों के दबाव में देश की सत्ता को आना चाहिए? मोदी जी हों या कोई किसी अन्य दल के कोई और प्रधानमंत्री हों, उसके विषय में ऐसी भाषा बोलकर जनता को भड़काना क्या उचित है?



विशेषत: इन कथित छात्राओं को देखकर बताएँ आप।

ये भी कहता हूँ कि, हैं तो ये हमारी देशज संतान ही, किंतु हमारे बच्चों को किसने इतना भड़काया और बहकाया है? कौन है जो हमारी इस मासूम छात्रशक्ति की लज्जा-लिहाज पर डाका डाल गया है? इनके सारे संस्कार अपहृत हो गए और हमें पता भी न चला। जॉर्ज सोरोस की सोच से बढ़ा ये आंदोलन है या अश्लीलता और देश विभाजन के दुष्कृत्य का नंगा नाच है?

ये महाशय मोदी और ये संघ, अपना झोला उठाकर कहीं भी, कभी भी चल पड़ेंगे। सोचना तो हमें है कि हम और कोई और ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी संघशक्ति कहाँ से लायेंगे जो हमें बारह वर्षों तक तमाम दुर्लक्ष्यों जैसे अद्वितीय आर्थिक विकास, गगन-पाताल को भेदने वाला इन्फ्रास्ट्रक्चर, मंगल मिशन, चंद्रमा मिशन, राममंदिर, अनुच्छेद 370, कश्मीर में शांति, असम-बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक, विदेशों में हमारा बड़ा सा बार्गेनिंग पॉवर, पाकिस्तान में भीतर तक घुसकर एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर आदि को साधकर भी दंगामुक्त शासन दे पायेगी? संघ परिवार के अतिरिक्त कोई भी पार्टी इनमें से एक भी काम करती तो देश भर में दंगे होते। खून की नदियाँ बहती। ऐतिहासिक मार-काट होती। कदाचित् (शायद) गृहयुद्ध भी हो जाता। शाहीन बाग से लेकर ये जंतर-मंतर तक, ये सब भारत में गृहयुद्ध भड़काने की तैयारी ही तो है। याद है न? इन्हीं लोगो के शब्द हैं - धारा 370 को छू कर देख लो, खून की नदियाँ बह जाएँगी और ये पाकिस्तानी भाषा भी याद होगी आपको - पंद्रह मिनिट के लिए देश की फौज और पुलिस को रोक लेना हम इस देश में तख़ूता पलट देंगे और यह भी कि मंदिर.. तारीख नहीं बताएँगे। ये सब इस संघशक्ति ने किया भी और खून की नदियाँ तो छोड़िए साहब; इन्होंने देश में परिंदे को पर भी न मारने दिए हैं। संघशक्ति से मोदी ने स्वयं को परिश्रमपूर्वक सिद्ध किया है, इस देश की जनता के समक्ष। 75 की आयु में अट्ठारह घंटे काम कर रहा ये बिना भगवे का सन्यासी हमारी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है। इन्होंने इस देश से बाबर और औरंगजेब का नाम मिटाया है और अरब में जाकर मदिरों के शिलान्यास से लेकर प्राणप्रतिष्ठा तक के दसियों आयोजन करवा दिए हैं। अरेबियन मुस्लिम योग-ध्यान के पीछे पागल हुए हैं तो इसी भारत सरकार की कलाकारी से ही हुए हैं। ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में या फूलफ़रूफ नीट परीक्षाओं के लिए नहीं था। यदि होता तो परीक्षाओं पर विश्व का सर्वाधिक सटीक और प्रभावी कानून आने के बाद ये आंदोलनकारी शांति से अलग हो जाते। ये आंदोलन उस संघ शक्ति के विरोध में है जो इस देश को कॉमन सिविल कोड की देने की तैयारी में लगी है।

झारखंड में सक्रिय 49 लाख के 8 इनामी माओवादियों का बीजापुर में सरेंडर

आत्मसमर्पण करने वालों में 5 महिला सहित कुल 8 माओवादी शामिल हैं.

बीजापुर। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बीजापुर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. झारखंड राज्य में सक्रिय प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के आठ इनामी माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया की आत्मसमर्पण करने वालों में पांच महिला और तीन पुरुष कैडर शामिल हैं। इन सभी पर कुल 49 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक उमेश गुप्ता ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी लंबे समय से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होकर संगठन के लिए काम कर रहे थे।



सुरक्षा बलों की लगातार प्रभावी कार्रवाई, माओवादी संगठन की कमजोर होती स्थिति, हिंसक एवं जनविरोधी विचारधारा से मोहभंग और छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी अश्विन ऊर्फ लच्छू, उम्र 30 वर्ष, निवासी सावनार पटेलपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर, पदनाम डीवीसीएम/जेडसीएमझारखण्ड राज्य अन्तर्गत दक्षिण जोनल कमेटी, इनाम 8 लाख रुपए, रंगा ऊर्फ सोहन, उम्र 30 वर्ष, निवासी पूसनार पेरमापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर, पदनाम झारखण्ड राज्य के दक्षिण जोनल कमेटी अन्तर्गत सराण्डा सब जोनल कमेटी सदस्य/डीवीसीएम, इनाम, 8 लाख रुपए, दोबा माड़वी ऊर्फ राहत, उम्र 25 वर्ष, निवासी तोयनार हिरपामाडपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर, पदनाम झारखण्ड राज्य के दक्षिण जोनल कमेटी अन्तर्गत सराण्डा सब जोनल कमेटी सदस्य/डीवीसीएम, इनाम 8 लाख रुपए, फगनी पोयम उर्फ रजनी, उम्र 28 वर्ष, निवासी दारमेर थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर, पदनाम – झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोल्हान एरिया कमेटी सदस्य एसीएम (एरिया कमेटी पार्टी सदस्या), इनाम 5 लाख रुपए, सूरज मुन्नी चम्पिया उर्फ सुबनी, उम्र 25 वर्ष, निवासी सावनार पटेलपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोल्हान एरिया कमेटी सदस्य एसीएम (एरिया कमेटी पार्टी सदस्या) इनाम 5 लाख रुपए, हिड़मे कड़ती उर्फ रीता, उम्र 27 वर्ष, निवासी गोमगुड़ा थाना पामेड़ जिला बीजापुर, पदनाम झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोल्हान एरिया कमेटी सदस्य एसीएम।

लगातार बारिश से नेशनल हाईवे-163 बाधित

निर्माणाधीन पुल के पास बना बना डायवर्जन बहा, तेलंगाना का संपर्क टूटा

बीजापुर। जिले के भोपालपटनम क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़क संपर्क व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। नेशनल हाईवे-163 पर निर्माणाधीन पुल के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्जन तेज बहाव की चपेट में आकर दो हिस्सों में बंट गया। इसके चलते इस मार्ग पर छोटे-बड़े सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है।



तारलागुड़ा पोटाकेबिन के आगे सड़क बंद होने से भोपालपटनम से तेलंगाना की ओर जाने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग बाधित हो गया है, इससे आम नागरिकों, व्यापारियों और मालवाहक वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे-163 पर कई स्थानों पर पुल और पुलियों का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण अवधि के दौरान यातायात सुचारु रखने के लिए अस्थायी डायवर्जन बनाए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और उफनते नालों के कारण ये डायवर्जन सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं।नेशनल हाईवे-163 छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्ग है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री वाहन, बसें, मालवाहक ट्रक और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन गुजरते हैं। इस बीच भारी बारिश से तारलागुड़ा के समीप निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया डायवर्जन बह गया। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी।

विशेष रूप से व्यापारियों, किसानों और दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन मार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में निर्माणाधीन पुलों के पास बनाए गए अस्थायी डायवर्जन हर वर्ष खतरे का कारण बनते हैं। तेज बारिश के दौरान इन मार्गों पर पानी का दबाव बढ़ते ही आवागमन बाधित हो जाता है।

लोगों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग से बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बार-बार सड़क बंद होने की स्थिति से बचा जा सके। मौसम विभाग ने भी क्षेत्र में और बारिश का अनुमान जताया है।

नाबालिग गाड़ी चालकों पर दुर्ग पुलिस की सख्ती, स्कूलों में चला चेकिंग अभियान

दुर्ग। पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विशेष ट्रैफिक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत शहर के स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख चौक-चौराहों पर लगातार सघन वाहन जांच की जा रही है। पुलिस का मुख्य फोकस उन नाबालिग छात्र-छात्राओं पर हैं। पुलिस के अनुसार हाल ही में चलाए गए अभियान में 600 से अधिक वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 67 पालकों को थाने बुलाकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें अपने बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन नहीं देने की समझाइश दी गई। इसके अलावा कई नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उनसे वचन पत्र भी भरवाया गया, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने देने का आश्वासन दिया। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि अभियान के दौरान पहली बार यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते



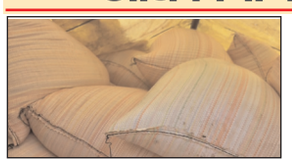
हुए पकड़ा जाता है, तो उसका सामान्य चालान काटा जाएगा और उसके परिजनों को थाने बुलाकर समझाइश दी जाएगी। साथ ही भविष्य में बच्चों को वाहन न देने की चेतावनी भी दी जाएगी। लेकिन यदि वही नाबालिग दोबारा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसके परिजनों के खिलाफ सीधे 25,000 के जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस का मुख्य फोकस उन नाबालिग छात्र-छात्राओं पर है, जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए सड़क पर निकलते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर गंभीर सड़क हादसे सामने आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।

पीडीएस चावल की तस्करी पर शिकंजा

खाद्य विभाग ने अनाज समेत जब्त किया वाहन

जगदलपुर। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए पीडीएस से भरे वाहन को जब्त किया है।खाद्य विभाग को कई दिनों ने अवैध रुप से पीडीएस चावल खरीदी और फिर तस्करी की शिकायतें मिल रही थी।इसी को लेकर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।जिस वाहन को खाद्य विभाग ने जब्त किया है उसमें 30 से 40 बोरी पीडीएस चावल लोड था।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पीडीएस चावल को दूसरे राज्य में खपाने की प्लानिंग



थी।सहायक खाद्य अधिकारी दिव्यारानी कार्यान्त ने बताया कि पीडीएस चावल से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा गया है। वाहन में करीब 30-40 बोरी चावल पाया गया है। बारिश की वजह से बोरियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। यह गाड़ी किराना व्यापारी सुनील गुप्ता की है। जो अनाज खरीदी बिक्री का काम करते हैं। पीडीएस चावल की अवैध खरीदी बिक्री और परिवहन करना कानूनन अपराध है। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है- दिव्यारानी कार्यान्त,सहायक खाद्य अधिकारी अधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा है कि इस बीपीएल कार्डधारियों और पात्रों को पीडीएस का चांवल समय पर मिले। लेकिन तस्करी जैसी घटनाएं सामने आती है। इसीलिए इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बस्तर में घटी इस घटना ने एक बार फिर सरकारी राशन वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जहा एक ओर हजारों गरीब परिवार अपने हिस्से के राशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

मोमोज के ठेले से करोड़ों की दौलत तकज फॉरेक्स ट्रेडिंग या करोड़ों की कथित ठगी

डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में सामने आया धोखाधड़ी का कथित लॉन्ग एशिया ट्रेडिंग ऐप मामला अब एक बड़े वित्तीय नेटवर्क की जांच का विषय बन गया है। निवेशकों के बयान, सामने आए दस्तावेज, वीडियो, फोटो और ऑडियो इस पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे संकेत मिल रहे हैं कि लोगों को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) ट्रेडिंग के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर देशभर में एक बड़ा निवेश नेटवर्क खड़ा किया गया। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार अगस्त 2024 में डोंगरगढ़ निवासी कुलजीत सिंह भाटिया, जोगेंद्र वर्मा और रायपुर निवासी अभय कुंडले ने देश के अलग-अलग शहरों में बड़े होटलों में सेमिनार आयोजित कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। इनमें कोलकाता, बलिया, पुणे, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कई शहर शामिल बताए गए हैं। निवेशकों को बताया जाता था कि XTB International Limited के माध्यम से ऑटोमेटिक फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी और सिर्फ 500 अमेरिकी डॉलर से निवेश शुरू कर हर महीने 8 से 10 प्रतिशत तक रिटर्न कमाया जा सकता है। साथ ही यह भरोसा भी दिया जाता था कि मूलधन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकेगा।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शुरुआत में उन्हें नियमित भुगतान मिलता रहा। इससे उनका भरोसा बढ़ा और उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को भी इस नेटवर्क से जोड़ दिया। बाद में रायपुर के एक होटल में आयोजित बड़े कार्यक्रम में भी यही दावा किया गया कि हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक कमाई कर रहे हैं। मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि शिकायत के अनुसार बाद में निवेशकों के खाते बिना किसी स्पष्ट लिखित सूचना के एक्सटीबी इन्टरनेशनल से एफसीएक्सएक्स इन्टलनेशनल लिमिटेड और फिर लॉग एसीया ग्रुप एनजेड लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिए गए। निवेशकों का आरोप है कि इस बदलाव के लिए उनकी पूर्व सहमति नहीं ली गई और उन्हें केवल मौखिक आश्वासन दिया जाता रहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है।

बाघ की खाल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

एमपी के वाइल्ड क्राइम ब्यूरो की टीप पर एक्शन



सूरजपुर। जिले में वन्यजीव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। वन विभाग ने मध्यप्रदेश के वाइल्ड क्राइम ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया है।आरोपियों के कब्जे से कुछ हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से वन्यजीव तस्करी से जुड़े एक सक्रिय नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वाइल्ड क्राइम ब्यूरो ने सूरजपुर क्षेत्र में वन्यजीवों की अवैध तस्करी की सूचना वन विभाग को दी थी। इसके बाद वन विभाग ने तत्काल दो विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई। टीम के अधिकारियों ने खरीदार बनकर तस्करों से संपर्क किया और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पकड़ लिया।कार्रवाई के दौरान तीनों आरोपियों के पास से बाघ की खाल तथा पेंगोलिन के शल्क बरामद किए गए। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बरामद बाघ की खाल करीब पांच से छह महीने पुरानी लग रही है।आरोपी इसे ऊंची कीमत पर बेचने की फिराक में थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़

16 लाख स्वीकृत लेकिन नहीं शुरू हुआ सड़क निर्माण

बालोद। भैसबोड़ गांव में 16 लाख रुपये की स्वीकृत सड़क का काम करीब 1 साल बाद भी शुरू नहीं सका है। लंबे वक्त से परेशानी का सामना कर रहे ग्रामीणों ने बुधवार को अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने मार्ग के बीच में ही धान की रोपाई कर दी। इस दौरान वह ट्रैक्टर लेकर भी मौके पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक, गांव में राम मंदिर से मड़ई चौक तक करीब 16 लाख 15 हजार रुपये की लागत से सड़क निर्माण के लिए मंडी बोर्ड से प्रशासनिक स्वीकृति 12 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। इसके बाद 4 सितंबर 2025 को वर्क ऑर्डर जारी हुआ था। तीन महीने में सड़क बनकर तैयार होनी थी, लेकिन लगभग 1 साल बीतने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। बरसात के मौसम में ग्रामीणों की परेशानी दोगुनी हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों का आवागमन मुश्किल हो चुका है। वर्षों की मांगों के बाद यहां सड़क बनने के लिए स्वीकृति मिली थी, वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ, मगर सड़क निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम होने से नियुक्ति का अधिकार नहीं

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि केवल मेरिट सूची में नाम शामिल होने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का कानूनी रूप से अधिकार हासिल नहीं होता। सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब सक्षम प्राधिकारी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है, तो मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकता। मामला सूरजपुर जिले के रामानुजनगर का है। यहां की निवासी देवेन्द्र कुमारी साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिला पंचायत सूरजपुर ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत सचिव के 11 पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर 2018 को विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) वर्ग से आवेदन किया था और चयन प्रक्रिया के बाद उसका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल था। सात साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने पर देवेन्द्र कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कृषि विरासत पीला-काला कोसरा व तिखुर को मिलेगा जीआई टैग

नारायणपुर। जिले के सुदूर वनांचल अबूझमाड़ की पारंपरिक कृषि और वनोंपजों को अब वैश्विक पहचान मिलने जा रही है। नारायणपुर जिले के तीन स्थानीय उत्पादों पीला कोसरा काला कोसरा और तिखुर को जीआई टैग दिलाने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पहला मौका है जब अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र की पारंपरिक फसलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने अबूझमाड़ के जनजातीय समुदाय की दीर्घायु, सुदृढ़ स्वास्थ्य और खान-पान पर विशेष शोध किया। अध्ययन में सामने आया कि स्थानीय ग्रामीणों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य आधार उनके दैनिक आहार में शामिल ये पारंपरिक मिलेट्स हैं। प्रमुख विज्ञानी डा. दीपक शर्मा के अनुसार इन तीनों ही उत्पादों में लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। वर्तमान में इनके अन्य पोषण और औषधीय गुणों की गहन प्रयोगशाला जांच जारी है।

एसईसीएल में माइन सेफ्टी एंड माइंड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय, बिलासपुर में सुरक्षित मन, सुरक्षित खदान विषय पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अभियान पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कर्मचारियों के मानसिक सशक्तिकरण, सकारात्मक कार्य संस्कृति तथा सुरक्षित कार्यस्थल के महत्व पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों के व्यक्तित्व विकास एवं कार्यस्थल पर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसईसीएल - इनर एक्सीलेंस सीरीज़ का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एसईसीएल एवं ब्रह्माकुमारीज़ के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हरीश दुहन रहे। मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्माकुमारीज़ के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बी.के. पीयूष भाई उपस्थित रहे।

सेवा सेतु से बैगा परिवार को मिला अंत्योदय राशन कार्ड

मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए नवीन सेवा सेतु पोर्टल का लाभ अब दूरस्थ एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों तक भी प्रभावी रूप से पहुंचने लगा है। इसी क्रम में जिला मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिला के जनपद पंचायत भरतपुर अंतर्गत निवासरत राजकली बैगा के परिवार का अंत्योदय राशन कार्ड सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक जारी किया गया। राजकली बैगा के परिवार द्वारा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अंत्योदय राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह सरल एवं पारदर्शी रही तथा निर्धारित समयावधि में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद पात्र हितग्राही को राशन कार्ड जारी कर दिया गया। इससे उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक रही।

5 साल से तीन महत्वपूर्ण विषयों के व्याख्याता नहीं

275 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट

धमतरी। कुरूद विकासखंड के भाठागांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। यहां पिछले पांच सालों से तीन महत्वपूर्ण विषयों के व्याख्याता नहीं हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मंगलवार को शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य और पालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है।

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों ने बताया कि स्कूल में 275 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन भौतिकी, हिन्दी और भूगोल जैसे तीन प्रमुख विषयों के व्याख्याता लंबे समय से पदस्थ नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को नियमित रूप से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। कई बार अन्य विषयों के



शिक्षकों से पढ़ाई करानी पड़ती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। पालकों ने बताया कि उनके बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। विषय शिक्षक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को दूसरे शिक्षकों से पढ़ना पड़ रहा है, जिससे पाठ्यक्रम समझने में कठिनाई आती है। लगातार पांच वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ने यह भी बताया कि विद्यालय केवल नियमित पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यहां ओपन बोर्ड परीक्षा केंद्र, जोन स्कूल केंद्र, निजी विद्यालयों का नोडल केंद्र और आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी इसी विद्यालय में किया जाता है। ऐसे में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी का असर केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक संचालन पर पड़ रहा है। समिति का कहना है कि यदि जल्द व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं की गई तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा। नए शैक्षणिक सत्र को देखते हुए प्रशासन से प्राथमिकता के आधार पर भौतिकी, हिन्दी और भूगोल विषय के व्याख्याताओं की पदस्थापना करने की मांग की गई है।इस मामले में धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि भाठागांव स्कूल में वर्तमान में 13 शिक्षक पदस्थ हैं।

अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ने पकड़ी रफ्तार

कांकेर। मंगलवार को क्षेत्र के युवाओं ने एकजुट होकर अंतागढ़ को जिला घोषित करने की मांग को लेकर व्यापक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अभियान को क्षेत्रवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होकर अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान के दौरान युवाओं के साथ-साथ महिलाएं, बुजुर्ग और विभिन्न वर्गों के लोग भी आगे आए। पढ़े-लिखे लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन दिया, जबकि निरक्षर लोगों ने अंगूठा लगाकर अपनी सहमति दर्ज कराई। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं, बल्कि अंतागढ़ की



वर्षों पुरानी मांग को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। उनका दावा है कि ब्रिटिश काल से अंतागढ़ एक महत्वपूर्ण तहसील रहा है और उस समय इसका प्रशासनिक महत्व भी रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उस दौर की कई तहसीलें आज जिले का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि अंतागढ़ अब भी उपेक्षा का शिकार है। आंदोलन में शामिल युवाओं ने जनप्रतिनिधियों पर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि विपक्ष में रहते हुए नेता अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को भुला देते हैं। उनका कहना है कि हर चुनाव में जिला बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सालों से जिला की मांग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष ध्यान नहीं दे रहा।

संक्षिप्त समाचार

भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, बाढ़ की स्थिति से निपटने सभी कलेक्टर अलर्ट



रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव होने के बाद भारी बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस परिस्थितियों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के सभी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनती है तो जरूरतमंदों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए। एक दिवसीय दिल्ली प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री साय ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बुधवार रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विश्व के सबसे बड़े दशरा पर्व 'बस्तर दशहरा' में अहम भूमिका निभाने वाले मांझी, चालकी और मुड़िया जनजाति के लोगों की राष्ट्रपति मुर्मु के साथ मुलाकात होगी। इस दौरान वह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री साय बुधवार को रायगढ़ दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह हर वर्ष बनोरा आश्रम में पूज्य बाबा का आशीर्वाद लेने जाते हैं। पावन स्थल पर 30 से ज्यादा वर्षों से पूज्य श्री संत नारायण तपस्या में लगे हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पात्र हितग्राहियों की समस्याओं का तत्परता के साथ निराकरण हेतु जिला प्रशासन निरंतर सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत नायकबांधा, जनपद पंचायत अभनपुर की तत्कालीन पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी तारक को निलंबित कर दिया है। शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राम पंचायत नायकबांधा में 15वें वित्त आयोग से कराए गए सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण के 04 कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत श्रीमती विजयलक्ष्मी तारक को त्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत अभनपुर रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

एम्स ने हाईटेक आंगनबाड़ी में किया बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर के कम्युनिटी नर्सिंग की टीम ने महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित हाईटेक आंगनबाड़ी पहुंच कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के लिए पोषक डाइट प्लान बनाने का तरीका बताया। टीम ने बच्चों को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक खुद को स्वच्छ और हाइजिन रखने के टिप्स भी दिए। इससे पूर्व कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी का महाराष्ट्र मंडल ने अपनी परंपरा के अनुरूप सूत की माला और मोमेंटो देकर सम्मान किया। टीम ने बारिश के मौसम में बच्चों की सेहत के प्रति रखे जाने वाली सावधानी व सजगता के बारे में अभिभावकों को बताया। टीम ने अभिभावकों को बच्चे के हाइजिन का विशेष ख्याल रखने और मानसून के हिसाब से न्यूट्रीशियन गाइडेंस का पालन करने की टिप्स भी दिए। कार्यक्रम में पहुंचीं स्वास्थ्य समिति की समन्वयक डॉ. कमल वर्मा ने महाराष्ट्र मंडल के सेवाभावी कार्यों की जानकारी सभी से साझा की।

पण्डरिया की रेंगाबोड व्यपवर्तन योजना के लिए 63.80 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कबीरधाम जिले के विकासखंड-पण्डरिया की रेंगाबोड (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना के कार्यों के लिए 63 करोड़ 80 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के निर्माण से 1620 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

प्रदेश में अब तक 485.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसूनी बादलों की चाल अलग-अलग अंचलों में अलग रंग दिखा रही है। मैदानी और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में जहां नदियां-नाले उफान पर हैं और जलाशयों में तेजी से जलभराव हो रहा है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 29 जुलाई 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 1 जून से अब तक औसतन 485.9 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले 10 वर्षों के औसत (515.9 मिमी) का 94.2 प्रतिशत है। केवल 29 जुलाई को ही प्रदेश भर में औसतन 38.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे कई जिलों में धान रोपाई के कामों में तेजी आ गई है। इस मानसूनी सीजन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला बारिश के मामले में प्रदेश में सबसे शीर्ष पर बना हुआ है। यहां अब तक सामान्य से लगभग दोगुनी यानी 195.5% (772.0 मिमी) वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी बादलों ने जमकर मेहरबानी दिखाई है।

पुलिस का जज्बा ही सुरक्षित, शांत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत

पत्रिका जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026 में मुख्यमंत्री साय ने उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित

रायपुर। पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा, विश्वास और सुशासन की सबसे मजबूत आधारशिला है। पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर, हर मौसम और हर चुनौती के बीच दिन-रात जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। उनके त्याग, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही आम नागरिक अपने घरों में निश्चिंत होकर जीवन जी पाते हैं। ऐसे समर्पित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान पूरे समाज का सम्मान है।

मुख्यमंत्री श्री साय बुधवार को राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित एक निजी सभागार में आयोजित जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026% कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे पुलिस बल के मनोबल और सेवा भावना का सम्मान है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के साहसी, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के बीच उपस्थित होकर विशेष आत्मीयता और गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन जिस निष्ठा से करते हैं, वह समाज के लिए प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायक उप निरीक्षक ज्ञानेश्वरी यादव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने 199 किलोग्राम भार उठाकर न केवल देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि यह सिद्ध किया है कि पुलिस बल के जवान सेवा के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी उपलब्धि पूरे प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्षों तक नक्सलवाद ने बस्तर के विकास की गति को बाधित किया। प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण यह क्षेत्र हिंसा और भय के कारण अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आज बस्तर विकास, विश्वास और परिवर्तन के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ रणनीति तथा राज्य



पुलिस और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लोकतंत्र, विकास और मानवता की रक्षा का अभियान था। हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना कठिन जंगलों में अभियान चलाया और प्रदेश को भयमुक्त बनाने का कार्य किया। यह विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अध्याय बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें कई बार अस्पतालों में नक्सल मोर्चे पर घायल पुलिस जवानों से मिलने का अवसर मिला। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उनके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि देश और प्रदेश की सेवा का अदम्य संकल्प दिखाई देता था। वे कहते थे कि स्वस्थ होते ही फिर से मोर्चे पर लौटेंगे और नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही अदम्य जज़्बा आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आया और इसी के परिणामस्वरूप प्रदेश नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त होने की दिशा में निर्णायक सफलता प्राप्त कर सका।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह समाज के सकारात्मक प्रयासों को सामने लाकर जनविश्वास को मजबूत करता है। पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और सेवा भावना को समाज के सामने लाने से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और युवाओं को भी राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता समाज में विश्वास और उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करती है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने कहा कि किसी मीडिया संस्थान द्वारा पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान किया जाना अत्यंत सराहनीय पहल है। पत्रकारिता समाज के सामने आदर्श स्थापित करती है और जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देती है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें समाज की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सकता है। डीजीपी श्री गौतम ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति से सबसे अधिक राहत उन परिवारों को मिली है, जिनके बेटे, बेटियां, पति या पिता वर्षों तक बस्तर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे थे। यह उपलब्धि पूरे पुलिस बल के साहस, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है।

जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026% के अंतर्गत पुलिसिंग में नवाचार, सामुदायिक पुलिसिंग, संवाद से समाधान, सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, ई-मालखाना प्रबंधन, पिंक पेट्रोल यूनिट, महिला सुरक्षा, वूमेन हेल्पलाइन, साइबर अपराध नियंत्रण, अनुसंधान एवं अन्वेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री आर. कृष्णा दास, रायपुर पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री रजत बंसल सहित अन्य अधिकारीगण, पुलिसकर्मी एवं उनके परिवारजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

दिल्ली में कांग्रेस की बैठक से पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का तीखा कटाक्ष

■ **बोले- पार्टी की प्रासंगिकता हुई खत्म, छत्तीसगढ़ में नहीं बचा कोई भविष्य**

रायपुर। कांग्रेस की दिल्ली में प्रस्तावित बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और उसमें कोई स्पंदन नहीं बचा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए चंद्राकर ने कहा कि वह अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं और डूबते हुए आदमी की तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

पूर्व मंत्री चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं और वह केवल छोटे-छोटे मामलों को बड़ा बनाकर पेश कर रही है। साथ ही ई20 फ्यूल, भोरमदेव मंदिर विवाद, भाजपा कार्यकर्ताओं के इस्तीफे और कांग्रेस के आंतरिक पत्र समेत कई मुद्दों पर भी उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को घेरा।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ई20 फ्यूल संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्राकर ने कहा कि वह अखबार पढ़कर मुद्दों पर जागरूक होते हैं और फिर बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस विषय में अदालत से अनुमति मिल चुकी है। उनके मुताबिक, कांग्रेस का राष्ट्रीय महत्व के विषयों से कोई सरोकार नहीं है और पार्टी केवल एक परिवार की ताजपोशी में लगी हुई है।

भोरमदेव मंदिर में पूजा-अर्चना को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है और उसकी



सोच सनातन विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धार्मिक मुद्दों पर केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती है।

भाजपा के 111 कार्यकर्ताओं के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर भी चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक मंडल के कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन दीपक बैज ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। उनके अनुसार, कांग्रेस तिल का ताड़ बनाने की राजनीति कर रही है क्योंकि उसके पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं।

कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए चंद्राकर ने कहा कि पार्टी जनकल्याण के मुद्दों से पूरी तरह दूर हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को आत्ममुग्ध पार्टी बताते हुए कहा कि उसके नेताओं को अब अपना-अपना ठिकाना तलाश लेना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोई नेता तेलंगाना जाए, कोई कर्नाटक जाकर रोजगार ढूंढे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।

कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन और कार्यक्रमों को लेकर जारी किए गए आंतरिक पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि पार्टी ने अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इमरजेंसी लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के केवल तीन-चार नेता अपने प्रचार-प्रसार में लगे हैं, जबकि बाकी नेताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है। उनके मुताबिक, किसी भी लोकतांत्रिक दल में इस तरह का प्रतिबंध उचित नहीं माना जा सकता।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर कांग्रेस का जश्न, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना: धरमलाल कौशिक

बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देशभर में समरसता संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की है। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के जश्न को लेकर बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने बयान भी दिया है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के जश्न पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस किस मुकाम पर है सभी देख चुके हैं।कांग्रेस की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है।

धरमलाल कौशिक ने कहा कांग्रेस अपने दम पर कोई बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं है। दूसरे संगठनों के आंदोलनों का श्रेय लेने का प्रयास करती है।जिस संगठन ने इस मुद्दे को उठाया, वह स्वयं अभी विधिवत पंजीकृत भी नहीं है।उसी संगठन की आवाज के बाद नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।

कौशिक ने कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज कांग्रेस पूरे देश में एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है।उन्होंने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस तीसरे, उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल में उसका कोई प्रभाव नहीं बचा है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपने बलबूते कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है और केवल मुख्यधारा की अन्य पार्टियों के पीछे चलकर अपनी



उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करती है।

आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी कार्यालय बिलासपुर से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर समरसता संकल्प अभियान चलाने की बात कही।विधायक धरमलाल कौशिक ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए बताया गया कि इसका उद्देश्य गुरु रविदास महाराज के समता, सामाजिक न्याय, सेवा, सद्भाव और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि गुरु रविदास महाराज किसी एक समाज के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के महान पथप्रदर्शक थे। उनके विचार आज भी विकसित भारत के निर्माण के लिए मार्गदर्शक हैं। अभियान के तहत 29 जुलाई को देशभर के मंदिरों में समरसता दीप महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कलश वंदन अभियान, संत संपर्क अभियान, समरसता यात्रा और छात्रावास संपर्क अभियान जैसे कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वाराणसी की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी देशभर के राज्यों, जिलों और गांवों तक पहुंचाई जाएगी।धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से समरसता का संदेश दिया जाएगा।

एआई के जमाने में विद्यार्थी स्वयं बेहतर भविष्य तय करें: रजत बंसल

रायपुर। स्थानीय महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं उन्हें महाविद्यालयीन जीवन, शैक्षणिक वातावरण और संस्थान की गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीक्षारम्भ-2026 कार्यक्रम का आयोजन उत्साह एवं गरिमापूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजत बंसल, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर, सभापति एवं समाजसेवी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री रजत बंसल ने



विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि महाविद्यालयीन जीवन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य की दिशा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए निरंतर सीखने, समय का सदुपयोग करने तथा समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रमोद दुबे ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनना है।

मंत्री राजवाड़े ने चांदनी बिहारपुर को दी एम्बुलेंस की सौगात

■ **28 ग्राम पंचायतों की 39 हजार से अधिक आबादी को मिलेगा लाभ**

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना जीवन रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए। नई एम्बुलेंस सेवा चांदनी बिहारपुर और आसपास के गांवों के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करेगी।

प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बुधवार को सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से नई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।



लगभग 18 लाख रुपये की लागत से उपलब्ध कराई गई यह एम्बुलेंस अब क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाएगी। इस पहल से 28 ग्राम पंचायतों में निवासरत 39 हजार 325 से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

अब तक चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना या प्रसव जैसी आपात परिस्थितियों में इलाज के लिए दूरस्थ शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार समय पर वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से अब मरीजों को त्वरित रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाना संभव हो सकेगा।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन महिलाओं, बच्चों और आमजन के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के साथ-साथ लोगों में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति विश्वास को भी सुदृढ़ करेगी।

मुख्य सचिव ने परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक ली

■ **सिंचाई परियोजनाओं को अधिक व्यवहारिक, टिकाऊ और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर दिया जोर**

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की 72वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जशपुर जिले के विकासखंड कुनकुरी अंतर्गत प्रस्तावित योजना के हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन शीर्ष कार्य, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं बहुद्देशीय उद्वहन सिंचाई योजना सहित बेमेतरा जिले की शिवनाथ नदी में ग्राम मोतिमपुर-बिरौदा एनीकट के बैराज में परिवर्तन एवं उद्वहन सिंचाई योजना के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित योजनाओं का पुनः री-मॉडलिंग एवं री-वर्क किया जाए, ताकि परियोजनाएं अधिक व्यवहारिक, टिकाऊ और संसाधनों-संरक्षण आधारित बन सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के निर्माण में जल संरक्षण, बेहतर वर्क मैनशिप और आधुनिक तकनीकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से नहर आधारित प्रणाली के स्थान पर समर्पित



पाइपलाइन प्रणाली की व्यवहार्यता का भी गहन अध्ययन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पाइप आधारित प्रणाली अधिक विश्वसनीय, जल की कम हानि वाली, कम लागत एवं समय में पूर्ण होने वाली हो सकती है तथा इससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी काफी कम होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना में ऑप्शन एनालिसिस अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन कर सबसे प्रभावी और किफायती मॉडल का चयन किया जा सके। साथ ही, परियोजनाओं की आगामी 5 से 10 वर्षों की संचालन एवं रखरखाव की रणनीति भी पहले से स्पष्ट रूप से तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि नए प्रस्ताव तैयार करने से पहले वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जिससे जनहितकारी परियोजनाओं का निर्माण सुनिश्चित हो सके। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लाठी और लोकतंत्र जेन जी ने दिखाई राह

पूनम आई. कौशिश

'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।' दिल्ली की सड़कों पर 37 दिनों तक चले निर्भीक, मुखर और डिजिटल दौर के युवा आंदोलन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समान, गुणवत्तापूर्ण और सार्थक शिक्षा केवल एक नीति का विषय नहीं, बल्कि युवाओं का संवैधानिक अधिकार है। कॉक्रोच जनता पार्टी के युवा कार्यकर्त्ताओं और सामाजिक कार्यकर्त्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने राजधानी को झकझोर दिया। नीट प्रश्नपत्र लीक और उससे जुड़े जवाबदेही के अभाव ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया तथा अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा सुधार की मांग गूंजने लगी। लेकिन इन मांगों का जवाब संवाद नहीं, बल्कि लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन, निर्मम पिटाई और भरोसे के टूटने के रूप में मिला। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रदर्शनकारियों को अपेक्षित राहत नहीं मिली। अदालत की टिप्पणियां थीं, ''हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है।'' एक अन्य टिप्पणी थी, ''हमें इसमें मत घसीटिए।'' ऐसी प्रतिक्रियाओं ने भी युवाओं को निराश किया। प्रदर्शन स्थल की चश्मदीद गवाह होने से स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वहां मौजूद युवा पुलिस की धमकियों से भयभीत नहीं थे। वे सरकार से कोई दान या कृपा मांगने नहीं आए थे। वे उस अधिकार की मांग कर रहे थे, जिसे वे संविधान द्वारा प्रदत्त अपना वैध अधिकार मानते हैं। ऐसा अधिकार, जिसे सत्ता की सुविधा के अनुसार दिया या छीना नहीं जा सकता। सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या समझा और उसका समाधान बल प्रयोग में खोजा। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे राजनीतिक अवसर के रूप में देखा। उसने प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन जताया और इसे आगामी चुनावों का मुद्दा बनाने में कोई देर नहीं लगाई। आखिर राजनीति में घायल सरकार की गंध से अधिक तेजी से नेताओं को और क्या आकर्षित कर सकता है? राजनीति में हर संकट किसी न किसी के लिए अवसर बन जाता है। चौंकाने वाली बात यह रही कि लाठियों ने केवल प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पूरे राजनीतिक वर्ग की मानसिकता को भी उजागर कर दिया, जो युवाओं का स्वागत तब तक करता है, जब तक वे तालियां बजाते रहें लेकिन जैसे ही वे सवाल पूछते हैं, उन्हें असुविधा महसूस होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग का उत्तर संवाद से नहीं, बल्कि बल प्रयोग से दिया। इससे केवल सरकार की असहमति के प्रति असहजता ही उजागर नहीं हुई, बल्कि यह भी सामने आया कि पूरा राजनीतिक वर्ग जनाक्रोश को लोकतांत्रिक चेतावनी की बजाय चुनावी पूंजी के रूप में देखने लगा है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा पाखंड पुलिस कार्रवाई नहीं था, बल्कि उसके बाद नेताओं द्वारा नैतिकता का चोला ओढ़ लेना था। चुनावों से पहले रोजगार, पारदर्शिता और अवसरों का वादा करने वाले वही नेता सत्ता में आने के बाद जनता की मांगों को चुनौती और अवज्ञा मानने लगते हैं। दरअसल सड़कों से जो सबसे बड़ा संदेश उभरकर सामने आया, वह यह कि आज का युवा उस राजनीति को अस्वीकार कर रहा है, जो अधिकारों को उपकार बनाकर प्रस्तुत करती है। वह उस राजनीतिक संस्कृति को भी चुनौती दे रहा है, जिसमें संवैधानिक अधिकारों को सत्ता की कृपा और जवाबदेही को वैकल्पिक गुण समझ लिया गया है। इतिहास बताता है कि लाठी किसी भी भीड़ को तितर-बितर कर सकती है लेकिन उस विचार को कभी समाप्त नहीं कर सकती, जिसका समय आ चुका हो।

भाजपा ने कॉजपा से क्यों टाला टकराव?

हरीश गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर से राजनीतिक दबाव कम करने के फैसले ने भाजपा के अनुभवी विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। यह कदम कई लोगों की उम्मीद से बहुत पहले ही उठा लिया गया, जिससे इस बात को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई कि आखिर किस वजह से सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार को ऐसी गंभीर खुफिया सूचनाएं मिली थीं कि छात्र प्रदर्शनों में असामाजिक तत्व घुस चुके हैं और वे आत्मदाह जैसी चरम घटना को अंजाम देने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि अगर ऐसी कोई भी घटना हो गई, तो इससे पूरे देश में अशांति फैल सकती है और विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा मिल जाएगा।

यह आंदोलन, जो शुरू में केवल कुछ जगहों तक सीमित था, धीरे-धीरे कई राज्यों की राजधानियों में फैल गया था। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, वामपंथी संगठनों और अन्य कार्यकर्ता समूहों सहित कई राजनीतिक समूह भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो गए थे, जिससे इस आंदोलन को एक बड़ा राजनीतिक रूप मिल गया।

सरकार की इस त्वरित प्रतिक्रिया और किसानों के आंदोलन के समय अपनाए गए रुख में जमीन-आसमान का अंतर है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सालभर चले किसान आंदोलन के दौरान, लगभग 700 से अधिक मौतों (जो बीमारी, दुर्घटनाओं, खराब मौसम और कुछ आत्महत्याओं के कारण हुई थीं) के बावजूद मोदी सरकार करीब एक साल तक अपनी बात पर अड़ी रही।

आखिरकार उसने कानून वापस लिए। लेकिन इस बार, सरकार ने महज 49 दिनों के भीतर ही घुटने टेक दिए। सरकार की सोच को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक आरएसएस माना जाता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने मोदी से बात की और आंदोलन को उग्र होने से रोकने के लिए जल्द से जल्द राजनीतिक समाधान निकालने का समर्थन किया।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान भागवत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 'हमें युवाओं को



आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए।' इस संदेश को व्यापक रूप से सरकार को सलाह के रूप में समझा गया। चाहे यह खुफिया चेतावनियां हों, संगठनात्मक सलाह हो, या राजनीतिक गणनाओं का संयोजन, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि टकराव को बढ़ने देने में जोखिम कहीं ज्यादा है।

क्या सरकार कॉजपा के प्रति नरम है?

कांग्रेस के कुछ समर्थक अब भी मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) कोई स्वत:स्फूर्त संगठन नहीं है, बल्कि भाजपा समर्थित एक राजनीतिक प्रयोग है। उनका मानना है कि इस पार्टी का गठन छात्रों के गुस्से को बांटने और विपक्षी दलों को आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ न मिलने देने के लिए किया गया था।

इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह साबित करना असंभव है। लेकिन सरकार का कॉजपा के प्रति असामान्य रूप से नरम रवैया निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और मोदी के अचानक पीछे हटने से इस धारणा में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

निशाना बनाए गए लोगों में से अधिकांश कॉजपा कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वे समर्थक थे जो स्वतंत्र रूप से आंदोलन में शामिल हुए थे। घटनाओं के क्रम ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। 6 जून को, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर बिना किसी पूर्व आवेदन के कुछ ही मिनटों में कॉजपा के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन को मंजूरी दे दी।

कहा जाता है कि कॉजपा नेता अभिजीत दीपके, जो उसी सुबह अमेरिका से आए थे, ने हवाई अड्डे पर ही आवेदन किया और उन्हें तुरंत मंजूरी मिल गई। गिरफ्तारी का सामना करने के बजाय, आयोजकों को आधिकारिक सहयोग मिला। यह सिलसिला तब भी जारी रहा जब कॉजपा ने एक और विरोध प्रदर्शन की अनुमति हासिल कर ली, जिससे 28 जून से सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का रास्ता खुल गया।

इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि 20 जुलाई को पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन के मंच को हटाने के बाद, अधिकारियों ने कथित तौर पर उसी रात इसके पुनर्निर्माण की निगरानी की। प्रत्येक घटना का एक तर्कसंगत कारण हो सकता है। हालांकि, सामूहिक रूप से, उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को बल दिया है कि अधिकारियों ने कॉजपा के प्रति असाधारण स्तर की आधिकारिक शिष्टाचारिता दिखाई है।

प्रधान के इस्तीफे से ओडिशा में चिंता!

हाल ही तक, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को भाजपा हाईकमान के दो सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। एक समय दोनों को पार्टी अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा था। लेकिन नेतृत्व ने अपेक्षाकृत कम चर्चित नितिन नवीन को चुनकर सबको चौंका दिया। तब से हालात बदल गए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर यादव के निजी सचिव समेत चार निजी कर्मचारियों को हटाए जाने के बाद से यादव निगाहों में आ गए हैं। वहीं, प्रधान अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। विडंबना यह है कि प्रधान 2024 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद ओडिशा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने का मौका भी चूक गए थे।

जहां कई लोगों को उम्मीद थी कि वे सरकार का नेतृत्व करेंगे, वहीं भाजपा ने मोहन चरण मांझी को चुनकर चौंकाने वाला फैसला सुनाया। मांझी के प्रशासन को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच, प्रधान का मंत्रिमंडल से बाहर होना उनकी राजनीतिक ताकत को कम नहीं करेगा,

बल्कि इससे उन्हें ओडिशा की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी मिल सकती है, एक ऐसी संभावना जो मौजूदा मुख्यमंत्री को शायद ही सुकून दे। प्रधान आरएसएस के भरोसेमंद व्यक्ति हैं और उनका कद कम नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी दो बार अपना पद छोड़ने की पेशकश की थी।

प्रह्लाद जोशी की सबसे बड़ी परीक्षा

धर्मेंद्र प्रधान ने भले ही विवादों के बीच शिक्षा मंत्रालय छोड़ा हो, लेकिन उनके उत्तराधिकारी प्रह्लाद जोशी को भी वही अनसुलझी समस्या विरासत में मिली है - राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)। भारत की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए 2017 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित एनटीए का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पेशेवर बनाना और सुव्यवस्थित करना था।

इसके विपरीत, यह पेपर लीक, व्यवस्था संबंधी विफलताओं और इसकी विश्वसनीयता पर बार-बार उठने वाले सवालों का पर्याय बन गया है। इस एजेंसी की सबसे बड़ी कमजोरी ढांचागत है। देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का संचालन करने के बावजूद, खबरों के मुताबिक इसमें केवल 25 स्थायी अधिकारी ही कार्यरत हैं।

यह छपाई, परिवहन और आईटी बुनियादी ढांचे के लिए निजी ठेकेदारों पर बहुत अधिक निर्भर है और संविदा कर्मचारियों की एक बड़ी टीम पर भी निर्भर है। इस निर्भरता के कारण गोपनीय प्रश्न पत्रों के प्रबंधन में बार-बार खामियां उजागर हुई हैं। इसकी तुलना संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से की जा सकती है।

दशकों से समान रूप से संवेदनशील राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं आयोजित करने के बावजूद, यूपीएससी ने कड़े नियंत्रण, सुव्यवस्थित प्रणालियों और न्यूनतम आउटसोर्सिंग के माध्यम से काफी हद तक बेदाग रिकॉर्ड बनाए रखा है। जोशी के लिए चुनौती केवल नुकसान की भरपाई से कहीं अधिक है। जब तक एनटीए में मौलिक सुधार नहीं किया जाता, प्रत्येक परीक्षा सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से पेचीदा क्षेत्र बना रहेगा और प्रत्येक शिक्षा मंत्री को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

पुराण दिग्दर्शन ....



विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

दूध दही 55, अन्नादि 80, मुजफ्फरनगर के इलाके में सब चीजों का 88, धामपुर नगीना 65, मुरादाबाद बरेली 105, श्रम्बाला के इलाके में (पुराना तोल) 36 तोले का।

इसी तरह हम नाप सम्बन्धी गज, कोस आदि पारिभाषिक शब्दों की इयत्ता में भी प्रत्यक्ष अन्तर देख पाते हैं। हमारे अपने प्रान्त में ही तीन प्रकार का गज बर्ताव में आता है। सोलह गिरह का छत्तीस इसी अंग्रेजी गज तो आज सभी जगह प्रचलित है परन्तु बढ़ई लोग एक चौबीस तसू का गज बर्तते हैं जिसे कि वे इभारती गज के नाम से पुकारते हैं और वह लगभग 32 इंच का होता है। जुलाहे लोग और प्राचीन सभ्यता के पुजारी किसान लोग एक तीसरा गज बर्ताव में लाते हैं जिसे वे कच्चा गज कहते हैं वह अन्यून 12 गिरह का ही होता है। कोस का छोटा बड़ापन तो प्रायः सभी यात्रियों को विदित है। मारवाड़ में जितनी दूरी को एक कोस बताते हैं देहली प्रान्त में उसे दो कोस और पूर्वीय पंजाब में चार कोस तक कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नाप सम्बन्धी परिमाण में भी तत्तत्प्रान्तीय व्यवस्था के अनुसार ही परिभाषा कल्पना करनी पड़ती है, अन्यथा न्यूनाधिक का गड़बड़ घुटाला हो जाना स्वाभाविक है।

ठीक इसी प्रकार पौराणिक भूगोल सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों की अर्थसीमा भी पौराणिक परिभाषा के अनुसार ही निश्चित करनो चाहिये । जिस तरह मुरादाबाद-वास्तव्य पुरुष के समक्ष बम्बइ निवासी सज्जन का यह कहना कि मैं आधा सेर घी प्रतिदिन खाता हूँ मुरादाबाद की परिभाषानुसार 105 तोले का सेर मानने की दशा में ही असम्भव जंच सकता है परन्तु बम्बई की परिभाषा के अनुसार केवल 28 तोले मात्र का सेर स्वीकार करने पर वह असम्भवता काफूर हो जाती है।

क्रमशः ...

शिव ने खाली कराई वाराणसी नगरी, दिवोदास के क्रोध से उजड़ गई थी काशी

आशुतोष गर्ग

किसी समय वाराणसी पर यदुवंशी राजा भद्रश्रेण्य का शासन था। उसके सौ पुत्र थे, किंतु राजा दिवोदास ने उन सबको परास्त कर दिया और वाराणसी पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया। दिवोदास के शासन में वाराणसी अत्यंत वैभवशाली हो गई। उधर, देवी पार्वती के साथ विवाह के बाद भगवान शिव कुछ समय तक हिमालय में ही रहे। परंतु, पार्वती जी की माता मैना को यह विवाह शुरू से ही पसंद नहीं था। वह प्रायः शिव और उनके गणों की निंदा करती थीं।

एक दिन उन्होंने पार्वती जी से कहा, 'उमा! तुम्हारे पति महादेव विचित्र स्वभाव के हैं। वह श्मशान में रहते हैं और उनके गण भी अनोखे आचरण वाले हैं। तुम्हें उनके साथ इतना कष्ट सहने की क्या



आवश्यकता है?' यह सुनकर माता पार्वती का हृदय आहत हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, 'नाथ! अब मैं अपने मायके में नहीं रहना चाहती। मुझे अपने घर ले चलिए।' तब भोलेनाथ ने विचार किया कि पृथ्वी पर ऐसा कौन-सा स्थान है, जहां वे दोनों स्थायी रूप से निवास कर सकें। उनकी दृष्टि वाराणसी पर पड़ी, जो तप, धर्म और सिद्धियों की भूमि थी। उस समय वहां राजा दिवोदास का शासन था। अतः शिवजी ने अपने प्रिय गण निकुंभ को बुलाकर कहा, 'तुम किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ऐसा उपाय करो कि वाराणसी नगरी मनुष्यों से रिक्त हो जाए। तब हम वहां निवास कर सकेंगे।'

निकुंभ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने नगर के एक नाई कंडुक को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, 'नगर के द्वार पर मेरी प्रतिमा स्थापित करो और मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। मैं तुम्हारा और नगरवासियों का कल्याण करूंगा।' अगले दिन सुबह कंडुक ने राजा की अनुमति लेकर नगर के प्रवेश द्वार पर निकुंभ की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई।

इस बीच राजा दिवोदास की रानी सुयशा भी पुत्र की इच्छा लेकर निकुंभ की पूजा करने पहुंची। उसने अनेक व्रत किए, प्रार्थना की, किंतु उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिला। वास्तव में निकुंभ जानबूझकर उन्हें वर नहीं दे रहे थे। उनके मन में यही विचार था कि राजा क्रोधित होकर कोई अनुचित कार्य करेगा, तभी वाराणसी मनुष्यों से रिक्त हो पाएगी।

लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद राजा का धैर्य टूट गया और उसने क्रोध में निकुंभ का मंदिर तुड़वा दिया। यह अपमान देखकर निकुंभ ने राजा को शाप दिया, 'दिवोदास! तुमने बिना किसी अपराध के मेरा स्थान नष्ट कराया है। इसलिए, यह समृद्ध वाराणसी शीघ्र ही जनशून्य हो जाएगी!' इसके बाद निकुंभ, महादेव के पास लौट आए और सारी घटना सुनाई। शिवजी व माता पार्वती वाराणसी में रहने लगे। यही स्थान आगे चलकर उनका प्रिय निवास बना। वहां कोई स्थायी भवन न होने के कारण पार्वती जी को प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने शिवजी से कहा, 'नाथ! यहां मेरा मन नहीं लगता। चलिए, किसी और स्थान पर चलते हैं।' यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, 'देवी! यह अविमुक्त क्षेत्र ही अब मेरा सनातन निवास है। मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो तुम अपने मायके जा सकती हो, किंतु मैं यहीं रहूंगा।'

यूएन महासचिव की रेस हुई दिलचस्प : भारत किसे देगा समर्थन?

अरुणिम भूयान

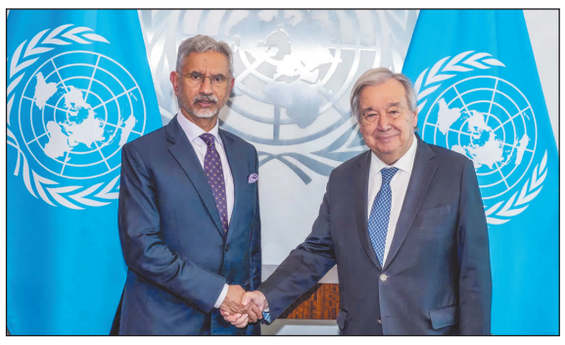
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अगले महासचिव पद की दौड़ भारत के राजनयिक दृष्टिकोण से एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर आगे बढ़ रही है। वैश्विक व्यवस्था में चल रहे युद्धों, भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बहुपक्षीय संस्थाओं पर गहराते अविश्वास के बीच, नई दिल्ली एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की तलाश में है जो प्रमुख महाशक्तियों और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सके।

रविवार को युगांडा के 75 वर्षीय ओलारा ओतुन्नु इस प्रतिष्ठित पद की दौड़ में शामिल होने वाले नवीनतम उम्मीदवार बन गए हैं। इस पद की दौड़ में शामिल होने वाले वह दूसरे अफ्रीकी और कुल सातवें उम्मीदवार हैं।

ओतुन्नु की उम्मीदवारी को जो बात दिलचस्प बनाती है, वह यह है कि उन्होंने खुद को संयुक्त राष्ट्र के एक अनुभवी सुधारक के रूप में पेश किया है। वह इस संस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहते हैं।

क्षेत्रीय रोटेशन (बारी-बारी से अलग-अलग क्षेत्रों को मौका देना) की अनौपचारिक व्यवस्था का काफी राजनीतिक महत्व है, भले ही यह कोई औपचारिक नियम नहीं है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से हैं और इसलिए वह पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह से आते हैं। उनके पूर्ववर्ती बान की-मून एशिया से थे, जबकि कोफी अन्नान अफ्रीका से थे।

इस वजह से इन तर्कों को बल मिला है कि अगला महासचिव चुनने के लिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र सबसे मजबूत स्थिति में है। इसके साथ ही पहली बार किसी महिला को महासचिव चुनने की संभावना भी इस चुनाव की एक बड़ी खासियत है। कुल सात उम्मीदवारों में से चार महिलाएं हैं। इससे एक अनोखी स्थिति पैदा हो गई है जहां लैंगिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय रोटेशन दोनों



एक साथ मेल खा रहे हैं, क्योंकि कई सबसे मजबूत महिला दावेदार उसी क्षेत्र (लैटिन अमेरिका) से हैं जिसे कई राजनयिक अगले कार्यकाल के लिए सबसे उपयुक्त मान रहे हैं।

वर्तमान दावेदारों में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के उम्मीदवारों का दबदबा है। इनमें चिली की मिशेल बाचेलेट, कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिनस्पैन, इक्वाडोर की मारिया फर्नांडा एस्पिरोसा और गुयाना की कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट शामिल हैं। इनके अलावा अर्जेंटीना के राफेल मारियानो ग्रॉसी भी दौड़ में हैं। वहीं, अफ्रीका से दूसरे उम्मीदवार सेनेगल के मैकी सॉल हैं।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत ग्रॉसी इस दौड़ में सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ हैं। अर्जेंटीना ने उन्हें नवंबर 2025 में नामांकित किया था, जिससे वे इस रेस के पहले औपचारिक उम्मीदवार बने। उनका दावा है कि वे महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संकटों को सुलझाने में सक्षम एक अनुभवी राजनयिक हैं।

चिली की पूर्व राष्ट्रपति बाचेलेट ने दो बार देश का नेतृत्व किया है और वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। उनकी वैश्विक पहचान, राजनीतिक अनुभव और यूएन में काम का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें सरकार और बहुपक्षीय मंचों दोनों का मजबूत अनुभव देता है। उनका दावा है कि वे यूएन की नैतिक साख और राजनीतिक स्वतंत्रता को बहाल कर सकती हैं।

कोस्टा रिका ने मार्च 2026 में ग्रिनस्पैन को नामांकित किया था। वे अंकटाड की महासचिव हैं और यूएन व अंतर-अमेरिकी विकास ढांचे में वरिष्ठ पदों पर रही हैं। उन्होंने खुद को विकास-केंद्रित बहुपक्षवादी के रूप में पेश किया है, जो वैश्विक सुरक्षा और ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की आर्थिक चिंताओं के बीच की खाई को पाट सकती हैं।

एस्पिरोसा इक्वाडोर की विदेश मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी पदों पर रही हैं और 2018-19 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष थीं। यूएन के शीर्ष स्तर पर काम करने का अनुभव उन्हें इस संगठन की संस्थागत ताकतों और कमजोरियों की गहरी समझ देता है। महासचिव पद की रेस में उनका दावा है कि वे सुधारवादी सोच वाली यूएन की ही सदस्य हैं, जो मानती हैं कि संयुक्त राष्ट्र को एक बड़े संस्थागत व राजनीतिक बदलाव की जरूरत है और एक महिला को इस बदलाव का नेतृत्व करना चाहिए।

रोड्रिग्स-बिर्केट इस रेस में कैरेबियन और ग्लोबल साउथ का एक अलग दृष्टिकोण लेकर आई हैं। गुयाना ने जून 2026 में उन्हें नामांकित किया था। वे एक अनुभवी राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सरकार और बहुपक्षीय कूटनीति दोनों का बड़ा अनुभव है। उनका मानना है कि एक छोटे देश की राजनयिक होने के नाते, वे विकासशील देशों, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों और कैरेबियन क्षेत्र की आवाज को वैश्विक मंच पर और मजबूत कर सकती हैं।

सॉल 2012 से 2024 तक सेनेगल के राष्ट्रपति रहे थे। उन्हें बुरुंडी द्वारा नामांकित किया गया था, जो उस समय अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष था। इसके बाद से उनकी उम्मीदवारी को सेनेगल के वर्तमान राष्ट्रपति बासिरू दियोमाये फाये का भी समर्थन मिल चुका है।

यह समर्थन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाये ने सॉल के बाद सत्ता संभाली थी और पहले वे सॉल के कुछ फैसलों के आलोचक रहे थे। फाये सरकार ने इस दावेदारी को अफ्रीका की सेवा में सेनेगल की उम्मीदवारी बताया है। सॉल ने खुद को एक अनुभवी अफ्रीकी राजनेता के रूप में पेश किया है, जो अफ्रीका और विकासशील दुनिया की चिंताओं को यूएन के एजेंडे के केंद्र में ला सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो, तब भी सुरक्षा परिषद का कोई एक स्थायी सदस्य उसे रोक सकता है।

सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस अपने वीटो पावर का उपयोग करके किसी भी उम्मीदवार को आगे बढ़ने से प्रभावी रूप से रोक सकते हैं। इसलिए, इस पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता होती है जो गंभीर भू-राजनीतिक मतभेदों और खेमों में बंटी दुनिया के सभी पक्षों को स्वीकार्य हो।

अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 2026 के इस चुनाव में भारत का दृष्टिकोण रणनीतिक हितों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार और एक ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता पर आधारित होने की संभावना है जो प्रमुख भू-राजनीतिक विभाजनों के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित कर सके। हालांकि, नई दिल्ली ने अभी तक इस रेस में शामिल किसी भी वर्तमान उम्मीदवार का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया है।

भारत एक ही समय में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख सदस्य है। ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की एक अग्रणी आवाज है, और वर्ष 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की दौड़ में भी शामिल है।

आज का इतिहास

1836 अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ।
1864 क्रेटर की लड़ाई: जनरल बर्न्सइड्स पीटर्सबर्ग के हमले में विफल रहे।
1865 क्रिसेंट सिटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका के तट से दूर, स्टीमरशिप जोनाथन, जो 1996 तक पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकने वाले सोने के सिक्कों की एक बड़ी खेप को ले जाता, एक अज्ञात चट्टान से टकराकर डूब गया, जिससे 225 लोगों की मौत हो गई।
1877 पीलेन की घेराबंदी में दूसरी लड़ाई शुरू हुई।
1909 राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया।
1912 जापान के सम्राट मीजी की मृत्यु हो गई और उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र योशीहिटो ने लिया, जिसे अब सम्राट तैशो के नाम से जाना जाता है।
1914 ऑस्ट्रिया की आर्टिलरीर बेलग्रेड शहर सर्बिया की राजधानी बना।
1916 जर्मन एजेंटों ने एक बड़े विस्फोट का कारण बना जब उन्होंने मैटरियल को प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों द्वारा इस्तेमाल होने से रोकने के लिए अजमेरिकन गोला-बारूद की आपूर्ति में तोड़फोड़ की।
1930 उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर मोंटेवीडियो में अपने घरेलू दर्शकों एस्तादियो सेंटेनारियो के सामने पहला फुटबॉल विश्व कप जीता।
1930 एनबीसी रेडियो पर देथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ।
1932 अमेरिका के लास एंजिल्स में दसवें आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई।
1938 पहला बच्चों का कॉमिक द बीनो ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ।
1942 जर्मन की सेना ने बेलारूस के मिंस्क में 25000 यहूदियों की हत्या की।
1966 आठवें फीफा विश्वकप में पश्चिम जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप फुटबॉल जीता।
1972 बैरीमोर न्यूयॉर्क शहर में बंद नहीं किया गया था मरने के लिए माना जाता है। इसने 325 प्रदर्शन किए हैं। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी।
1974 वाटरगेट कवर-अप में राष्ट्रपति निक्सन को महाभियोग लगाने के लिए, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने 3 और उच्च अपराधों और दुष्कर्मों के अंतिम आरोप पर वोट दिया।
1980 वनूआटो देश को स्वतंत्रता मिली।
1982 सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।

सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की इनसाइड स्टोरी

अभिनय आकाश

आज बात उस सवाल की, जिसने देश के लाखों छात्रों और युवाओं के दिल में एक कसक छोड़ दी है। लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जिन्होंने नीट के छात्रों की आवाज़ बनकर 26 दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं उठाया, जब उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ा... तो जश्न की जगह सन्नाटा और सवालों का बवंडर खड़ा हो गया! अजीबोगरीब मोड़ देखिए जो लोग 26 दिन से सोनम वांगचुक को कोस रहे थे, आज वही उन्हें 'महान' और 'समझदार' बता रहे हैं। जो छात्र, जो समर्थक कल तक उनके नाम का नारा लगा रहे थे, आज वही दबी ज़ुबान में पूछ रहे हैं- सोनम सर, ये क्या कर दिया? क्या यह बेवफ़ाई है? तो आज सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यही है-क्या सोनम वांगचुक ने छात्रों का भरोसा तोड़ा या फिर उन्होंने दूरदर्शिता और समझदारी दिखाई? क्या सोनम सच में बेवफ़ा हैं... या फिर आंदोलन की बाज़ी पलटने वाले सबसे समझदार खिलाड़ी? आइए, आज के एमआरआई में इसी गुत्थी की इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठाते हैं।

लोकतंत्र में प्रतिरोध का मतलब है अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाना। गलत के खिलाफ बोलना और देश चलाने का जिम्मा लेने वालों से जवाबदेही तलब करना। भारत का इतिहास ऐसे ही सफल जन आंदोलनों से लिखा गया है। आजादी की लड़ाई से लेकर 70 के दशक के जेपी मूवमेंट और फिर निर्भया आंदोलन तक हर बड़े बदलाव की नींव सड़क पर ही रखी गई है। जब देश का नौजवान सड़क पर उतरता है तो उसके सीने में सिस्टम के खिलाफ एक जायज आग होती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच शब्द देते हैं। एक आदमी कॉकरोच के नाम से मीम पेज बनाता है। फॉर्म भरवाता है। इंडिया आता है। 4 500 700 लोग नजर आते हैं। आठ दिन बाद सोनम वांगचुक जैसा चेहरा आता है। एक मीम पेज इंस्ट्राग्राम पेज सडनली एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। देश दुनिया में सबकी निगाहें जाती हैं। भीड़ बढ़ने जा लगती है। हालत यह होती है कि जनता सड़क से संसद जाने को तैयार हो जाती है। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के सताए लाखों स्टूडेंट्स ने जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर डेरा डाला तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के व्यंग से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने का जिम्मा लिया था। लोग समर्थन भी कर रहे थे और 20 जुलाई को जब चलो संसद का नारा सीजेपी लीडरशिप ने दिया तो देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे। तब तक भी आंदोलन में एक गजब की मासूमियत थी। बच्चे फूल बांट रहे थे। भारतीयवायु सेना भर्ती

अपनी मांगों को लेकर साफ शब्दों में गुजारिश कर रहे थे। यह सोचकर कि सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन जुलाई के आखिरी हफ्ते तक आते-आते इस शांतिपूर्ण प्रतिरोध की तस्वीर अचानक बदल गई। पुलिस और छात्रों के बीच खूनी झड़पें हुई। मीडिया के कैमरे तोड़े गए और पुलिस की गाड़ियों पर तलवारें



लहराई गई। सीजेपी का आंदोलन 6 जून को शुरू हुआ था। 28 जून को सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के साथ ही इसे एक मजबूत नैतिक केंद्र मिल गया। लेकिन सरकार ने हफ्तों तक इन छात्रों की कोई सुध नहीं ली। कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खोला गया। इसके उलट 18 जुलाई को पुलिस ने वाकचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। जब आप एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मांग को पुलिस के बूटों तले कुचलने की कोशिश करते हैं तो सड़क पर गुस्सा फटना तय हो जाता है। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दिन हालात बेकाबू हो गए। 1400 पुलिसकर्मियों की घेराबंदी, बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोलों ने दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। दर्जनों छात्रों के सर फूटे। जब सत्ता संवाद के बजाय डंडे की भाषा बोलती है तो भीड़ का सब्र भी जवाब दे देता है।

23 जुलाई की आधी रात के कुछ देर बाद, वांगचुक ने 26 दिनों से चल रहा अपना अनशन खत्म किया। राजधानी के मेदांता अस्पताल का एक वीडियो दिखाता है कि यह सब कैसे हुआ। केंद्रीय मंत्री नड्डा और सिंह का हाथ थामे हुए वांगचुक ने कहा कि अपना अनशन खत्म करके मैं आभारी और खुश हूँ। धन्यवाद। फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा गीतांजलि हमेशा मेरे साथ रही हैं। मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहता, बल्कि अपनी भावनाएं ज़ाहिर करना चाहता हूँ। बाद में जेपी नड्डा वांगचुक को सरकार के आश्वासन पढ़कर सुनाते हुए दिखे। मंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई, 2026 को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ़ केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक है। सरकार पहले ही बातचीत के ज़रिए पेपर लीक और परीक्षाओं से जुड़े शिक्षा सुधारों का समाधान निकालने का भरोसा दे चुकी है। इसके अलावा, सरकार हाल ही में हुए नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवज़ा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का कोई ज़िक्र नहीं किया गया, जो 28 जून को भूख हड़ताल शुरू करते समय वांगचुक की शुरुआती मांग थी।

इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा मजबूती तब मिली जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक तरह से कहें तो उस दिन के बाद सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट की रीड बन गए थे। क्योंकि सोनम वांगचुक के जुड़ने के बाद वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में आए जो दरअसल पर्यावरण को बचाने की देख रखते हैं। एक गंभीरता उन्होंने गंभीरता उन्होंने दे दी इस प्रोटेस्ट को। मगर लंबे वक्त के बाद अब लगभग 26 दिन के अनशन के बाद भूख हड़ताल के बाद। अब उन्होंने मतलब जूस पिया वो भी जेपी नड्डा के हाथ से। जेपी नड्डा के हाथ से इस इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि उसी सरकार के खिलाफ यह लोग लगातार आवाजें उठा रहे थे। इस मुलाकात का एक वीडियो जारी होता है। जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोनम वांगचुक को जूस पिला रहे हैं। सिर्फ जेपी नड्डा ही वहां पर नहीं होते बल्कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय में जो राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की भी मौजूदगी होती है। सरकार ने बताने की कोशिश की कि पीएमओ से भी एक मिनिस्टर को भेजा गया है।

जेपी नड्डा भी अंग्रेजी में अपनी बात रख रहे हैं और सोनम मानचुक भी अपनी बात को अंग्रेजी में ही रखा है। तो कुछ दो ढाई मिनट का वीडियो है। दोनों साइड्स का जहां वो सेटिस्फेक्शन खोजना चाहती थी वो आपको सुनने को मिल जाएगा। जेपी नड्डा भरोसा दिलाते हैं कि सरकार पॉजिटिव है। मतलब सरकार की नियत है कि जो जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जो पीसफुल कर रहे थे उनके खिलाफ हम मुकदमा नहीं लिखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव हैं। मतलब हम यह करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने 20 तारीख को मार्च किया उन पर भी मुकदमे या कोई पनिटिव एक्शन ना हो उसे लेकर भी सरकार पॉजिटिव है। जेपी नड्डा ये भी कहते हैं कि जो विक्टिम ऑफ पेपर लीक जिन बच्चों ने अपना जीवन समाप्त किया नीट पेपर लीक होने के बाद में रीट से पहले 20 बच्चे हैं। उनके लिए सूटेबल कंपनसेशन को लेकर भी सरकार पॉजिटिव है। गौरतलब है कि सोनम वागंचुक ने पिछला खत लिखा था उसमें उन्होंने यही कहा था कि लगातार सत्ता के और विपक्ष के सांसद मुझसे संपर्क कर रहे हैं। आग्रह कर रहे हैं कि मैं अपना अनशन समाप्त कर दूं और मैं इस बारे में गंभीरता से सोचूंगा। मैं कर दूंगा यह। यदि सरकार पहले उन्होंने कहा पहले इस्तीफे की मांग की। फिर उसके बाद उन्होंने यह कहा कि यदि सदन में चर्चा हो जाए और मुझसे आकर के कोई अस्पताल में मिल ले। अब जो आखिरी हालिया खत था उसमें उन्होंने लिखा था कि यदि सरकार यह वादा कर दे कि जिन बच्चों ने आंदोलन किया है उन पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। उनको उस चीज के लिए सजा नहीं दिया जाएगा तो फिर मैं अनशन छोड़ूंगा। तो वो बातें होती दिख रही हैं।

गुरुवार रात 11:52 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेल्फी वीडियो संदेश पोस्ट करके सीधा छात्रों से संपर्क साधा और नीट पेपर लीक विवाद के बीच उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। यह स्वीकार करते हुए कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई का वादा किया। इसमें शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा एक प्रस्तावित कानून पर निर्णय लेना भी शामिल है, जिसमें परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और कड़े दंड का प्रावधान है। प्रधानमंत्री का यह प्रयास उनके संचार के पारंपरिक तरीके से काफी अलग था।

पेपर लीक पर राजनीति से नहीं बनेगी बात

कांतिलाल मांडोत

देश में जब भी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है तो सबसे पहले लाखों युवाओं के वर्षों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है और विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करता है। प्रदर्शन होते हैं इस्तीफों की मांग उठती है और कुछ समय बाद कोई नया मुद्दा सामने आते ही पूरा विवाद धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जिस मूल समस्या ने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया था उसका स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। हाल के घटनाक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी राजनीतिक दबाव और छात्र आंदोलन के बीच हुआ। सरकार ने इसे परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया निर्णय माना तो विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसी मंत्री के इस्तीफा देने भर से पेपर लीक की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि उत्तर नहीं है तो फिर देश को केवल राजनीतिक घटनाक्रम पर नहीं बल्कि व्यवस्था में व्यापक सुधार पर ध्यान देना होगा। पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है। पिछले दो दशकों में देश के अनेक राज्यों में शिक्षक भर्ती पुलिस भर्ती पटवारी भर्ती मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। यह भी सत्य है कि अलग-अलग समय में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसलिए इस समस्या को केवल किसी एक दल या एक व्यक्ति की विफलता बताना वास्तविकता से आंखें मूंदने जैसा होगा। यूपीए सरकार के समय भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगे थे। बाद के वर्षों में भी विभिन्न राज्यों में अनेक भर्ती परीक्षाएं विवादों में रहीं। राजस्थान इसका प्रमुख उदाहरण रहा है जहां शिक्षक भर्ती परीक्षाओं सहित कई मामलों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उस समय भी जिम्मेदारी तय करने को लेकर राजनीतिक विवाद हुए लेकिन व्यवस्था में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं पूरी तरह रुक सकें। आज भी लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य से पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पेपर लीक अब कुछ व्यक्तियों की शरारत नहीं बल्कि संगठित अपराध का रूप ले चुका है। इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर छपाई परिवहन परीक्षा केंद्र और डिजिटल माध्यमों तक कई स्तरों पर अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय रहता है। करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन के कारण यह एक लाभकारी आपराधिक कारोबार बन चुका है। जब तक इस पूरे नेटवर्क को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक केवल छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे राजनीतिक परिस्थितियां अपनी जगह हो सकती हैं। छात्र आंदोलन विपक्ष का दबाव और चुनावी समीकरण भी किसी लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हुआ कि देश का युवा अब पारदर्शिता और जवाबदेही चाहता है। वह केवल आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहता है। यही कारण है कि पेपर लीक का मुद्दा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि रोजगार और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया। यह भी ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी आंदोलन बहुत तेजी से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले सकता है। विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की प्रतिक्रियाएं हों या विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन यह लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा है। लेकिन किसी भी आंदोलन या उसके पीछे की परिस्थितियों को लेकर बिना ठोस प्रमाण के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में तथ्यों के आधार पर ही चर्चा और निर्णय होने चाहिए।

जेन-जी के मकड़जाल में फंसी सरकार?

सनत जैन

नीट पेपरलीक मामले को आधार बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन बड़ी तेजी के साथ सारे देश में फैल गया। आंदोलनकारी अपने-अपने घरों से निकलकर प्रदर्शन में शामिल हुए। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर में शुरू हुआ यह आंदोलन देखते ही देखते सारे देश में फैल गया। 20 राज्यों के लगभग 300 स्थानो पर जेन-जी के युवा जिनकी उम्र 16 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में थी। बड़ी संख्या में अपने मां-बाप के विरोध के बावजूद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। जंतर-मंतर में जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया, उसने सभी को चौंका दिया। सरकार को भी चिंता हुई, आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए सरकार सक्रिय हुई। सबसे पहले सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करके शर्तों के साथ यह आंदोलन खत्म कराने में सरकार सफल रही। ऐसा लगा कि यह मामला निपट गया है।

आंदोलन खत्म करने सरकार ने जो आश्वासन काकरोंच जनता पार्टी को दिए थे, उन आश्वासनों को पूरा करने के स्थान पर सरकार ने सारा ध्यान नीट पर लगा दिया है। सरकार ने ताबड़-तोड़ तरीके से एंटी पेपर लीक बिल संसद में पेश कर दिया है। 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया है। सरकार को लगता है, इस बिल के बाद जेन-जी का यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। सरकार यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं के बारे में कॉकरोच के रूप में टिप्पणी करना, उनकी डिग्री और बेरोजगारी पर कटाक्ष करना, करोड़ों युवाओं को उद्वेलित कर देगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। पिछले एक दशक में परीक्षा पेपर लीक होने, भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होने के बाद भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भारत में लगभग 30 करोड़ युवा इन दिनों बेरोजगारी के शिकार हैं। लाखों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री लिए युवक ऑनलाइन डिलीवरी,



मोटर साइकिल पर सवारी ढोने और अन्य छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर हैं, ताकि वह अपना पाकिट खर्च निकाल पाएं।

सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था। केंद्र एवं राज्य सरकारों के करोड़ों सरकारी पद खाली हैं, उनमे भर्ती नहीं हो रही है। संविदा में ठेकेदारी प्रथा में युवाओं को जो 15000 की नौकरी मिल रही है। ठेकेदारी प्रथा में होने के कारण दो से 3000 रूपये उनके ठेकेदार काट लेते हैं। शिक्षा महंगी होती जा रही है। युवाओं को बड़े-बड़े सपने निजी कॉलेजों में दिखाए जाते हैं। उसके बाद जब वह डिग्री लेकर निकलते हैं, तो वह सपने, सपने ही रह जाते हैं। हर जगह परीक्षा के लिये कोचिंग, परीक्षा शुल्क के रूप में करोड़ों की कमाई और उसके बाद प्रवेश में भ्रष्टाचार, एक ऐसा कैंसर हो गया है, जो इलाज के बाद भी कम होने के स्थान पर फैलता चला जा रहा है। केंद्र सरकार इस आंदोलन को फोरी तरीके से ले रही है।

नीट परीक्षा का पेपर लीक होना इस आंदोलन में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह आंदोलन युवाओं के भविष्य के प्रति चिंता और उनकी नाराजी को बता रहा है। युवाओं की समस्याओं का समाधान निकालने में ना तो केंद्र सरकार की रुचि है, नाही राज्य सरकारों की रुचि है। चुनाव के समय युवाओं को बड़े-बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं, उसके बाद जब यही युवा सड़कों पर आकर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं।

भारत का 30 करोड़ से ज्यादा युवा इस समय नाराजी के उस दौर से गुजर रहा है, जहां पर उसे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। न्यायपालिका से भी युवाओं को कोई राहत नहीं मिलती है। गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। सभी जगह पारदर्शिता खत्म है। ऐसी स्थिति में जेन-जी को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सड़कों पर आकर लड़ना पड़ रहा है। पहली लड़ाई उसने अपने घर पर लड़ी, माता-पिता उसे धरना प्रदर्शन और आंदोलन में जाने से रोकते रहे। वह अपने परिवार से विद्रोह करके सड़कों पर आ गया है। उसका जो डर और भय था, वह विद्राह में बदल गया है। उसने लड़ना सीख लिया है, उसे एहसास हो गया है, जब तक वह अपने भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। भारत के इतिहास में 1973-74 में गुजरात से छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। जो संपूर्ण क्रांति का प्रतीक बना। इंदिरा गांधी की सत्ता इस आंदोलन के बाद चली गई थी। 1979 से 85 के बीच में असम में छात्र आंदोलन हुआ। 1990 में मंडल के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। 2011-12 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। हर आंदोलन के बाद केंद्र और राज्यों की सरकार को जाना पड़ा है। हर छात्र आंदोलन ने सत्ता को झुकाया है। जो भी परिवर्तन देश में हुए हैं, उन सब का साक्षी युवा रहा है।

1942 का आंदोलन भी युवाओं ने लड़ा था। कॉकरोचों का यह आंदोलन केवल नीट पेपर तथा एडमिशन की लड़ाई नहीं है। यह सभी वर्ग के युवाओं की लड़ाई है। जो बेरोजगारी और भविष्य के लिए सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को इस मामले में संवेदनशीलता, विश्वसनीयता एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव की जरूरत है। भारत में शिक्षा रोजगार को बढ़ाने वाली हो। शिक्षा का आशय आत्मनिर्भर बनना होता है। अभी जो डर और भय का माहौल है, ऐसे माहौल में बौद्धिक विकास रुक गया है। युवाओं ने जंतर-मंतर में आंदोलन करके बता दिया है, वह हर किस्म से सक्षम हैं, जो चाहें वह कर सकते हैं, डर-भय युवाओं का अब खत्म हो गया है। सारा देश इस समय बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। समस्त राजनीतिक दलों को इस मामले में जिम्मेदारी के साथ आगे आना होगा।

आखिर क्या हो प्रदर्शन प्रोटोकॉल ताकि न होने पाए उपद्रव?

कमलेश पांडे

किसी भी लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार और जन-जीवन की सुरक्षा—दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए जो शांतिपूर्ण विरोध की रक्षा करे, लेकिन हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ को रोके। गत दिनों कॉकरोच जनता पार्टी/सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली या अन्य राज्यों में जो कुछ हुआ, उससे यह प्रश्न एक बार पुन: प्रासंगिक हो चुका है।

चूंकि इससे पहले भी अनेक प्रदर्शन उग्र हुए, जिससे सरकारी व निजी संपत्ति की क्षति हुई, पर कार्रवाई वही लीपापोती वाली या फिर दलगत प्रतिशोध जैसी, जबकि दोनों अनुचित हो। ऐसी कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। जानकारों की राय में एक संतुलित प्रदर्शन प्रोटोकॉल इस प्रकार हो सकता है-

पहला, पूर्व अनुमति और उत्तरदायित्व: आयोजकों को समय, मार्ग, अनुमानित भीड़ और जिम्मेदार पदाधिकारियों की जानकारी पहले से देनी चाहिए।

दूसरा, शांति की लिखित प्रतिज्ञा: आयोजक यह लिखित आश्वासन दें कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। हिंसा होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करेंगे।

तीसरा, निर्धारित स्थान और मार्ग: प्रदर्शन के लिए तय मार्ग और स्थान हों, ताकि अस्पताल, स्कूल, एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

चौथा, वीडियो रिकॉर्डिंग और बॉडी कैमरा: पुलिस और आयोजकों—दोनों की ओर से रिकॉर्डिंग हो, ताकि बाद में यह स्पष्ट हो सके कि हिंसा किसने शुरू की।

पांचवां, हथियार और खतरनाक सामग्री पर प्रतिबंध: लाठी, पेट्रोल, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ या अन्य खतरनाक सामान लाने पर रोक हो।

छठा, चरणबद्ध पुलिस कार्रवाई: पुलिस पहले संवाद करे, फिर चेतावनी दे, उसके बाद ही



आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम बल का प्रयोग करे।

सातवां, तोड़फोड़ की भरपाई: यदि जांच में साबित हो कि किसी व्यक्ति या समूह ने सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो उससे क्षतिपूर्ति वसूली जाए। केवल भीड़ में मौजूद होने के आधार पर किसी पर दायित्व न डाला जाए।

आठवां, उकसाने वालों की पहचान: सीसीटीवी, ड्रोन और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और हिंसक तत्वों में स्पष्ट अंतर किया जाए।

नौवां, स्वतंत्र निगरानी: बड़े प्रदर्शनों में न्यायिक या स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की व्यवस्था हो, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों—दोनों की जवाबदेही बनी रहे।

दसवां, समान कानून, समान अनुपालन: नियम किसी भी संगठन, दल, जाति या विचारधारा के लिए अलग-अलग नहीं होने चाहिए। कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन ही जनता का विश्वास बढ़ाता है।

ऐसा प्रोटोकॉल लोकतंत्र को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत करेगा। इससे नागरिकों का शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा और समाज को हिंसा, आगजनी तथा सार्वजनिक संपत्ति की क्षति से भी बचाया जा सकेगा।

ज्वलंत प्रश्न: प्रोटोकॉल टूटने पर राजनीतिक दलों और संगठनों के नेतृत्व व संलिप्त तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए या नहीं?

चूंकि यह एक नीतिगत और कानूनी प्रश्न है। लिहाजा इसका संतुलित उत्तर यह है कि सिर्फ नेतृत्व के पद पर होने के कारण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि कानून के अनुसार उनकी जिम्मेदारी या संलिप्तता सिद्ध होती है, तो अवश्य होनी चाहिए।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्न सिद्धांत उचित माने जा सकते हैं-

एक, यदि नेतृत्व ने हिंसा के लिए उकसाया, उसका निर्देश दिया, या हिंसक गतिविधियों की योजना में शामिल था, तो उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।

दो, यदि न्यायिक प्रक्रिया या जांच से यह सिद्ध हो कि नेतृत्व ने जानबूझकर हिंसा रोकने के अपने दायित्व की अनदेखी की, तो प्रासंगिक कानूनों के तहत जवाबदेही तय की जा सकती है।

तीन, यदि प्रदर्शन की शर्तों का गंभीर उल्लंघन हुआ और आयोजक ने सहयोग नहीं किया, तो भविष्य में अनुमति पर प्रतिबंध, आर्थिक दंड या अन्य वैधानिक कार्रवाई जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

लेकिन केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी दल या संगठन का प्रमुख है, उसके विरुद्ध बिना साक्ष्य के कार्रवाई करना कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

सबसे उपयुक्त व्यवस्था यह होगी कि व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी साक्ष्य के आधार पर तय हो। संगठनात्मक जिम्मेदारी अलग से तय हो, जैसे क्षतिपूर्ति या प्रशासनिक दंड। सभी दलों और संगठनों पर एक ही नियम समान रूप से लागू हों। अंतिम निर्णय स्वतंत्र जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हो, न कि राजनीतिक दबाव में। इस प्रकार, कठोर जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन वह साक्ष्य, निष्पक्ष जांच और विधि के शासन पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल पद या राजनीतिक पहचान पर।

आंदोलन आपका हो, एजेंडा किसी और का नहीं

रवि प्रकाश

जंतर-मंतर पर बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, उसने केवल एक आंदोलन की तस्वीर नहीं दिखाई, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के सामने खड़े एक बड़े प्रश्न को भी उजागर कर दिया। वह प्रश्न है- क्या हर वह व्यक्ति, जो किसी आंदोलन की भीड़ में दिखाई देता है, वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए वहां मौजूद होता है? उत्तर है- जरूरी नहीं। किसी भी आंदोलन में भीड़ दिखाई देती है, लेकिन भीड़ कभी एक जैसी नहीं होती। वहां अलग-अलग विचारों वाले लोग होते हैं, अलग-अलग संगठनों के लोग होते हैं, अलग-अलग राजनीतिक सोच वाले लोग होते हैं, अलग-अलग हितों वाले लोग होते हैं। कोई सचमुच पीड़ितों के साथ खड़ा होता है, कोई अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई राजनीतिक अवसर तलाशता है, कोई केवल भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो किसी भी जनभावना को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का अवसर खोजते हैं। यहीं से युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। यदि आपकी मांग न्यायसंगत है, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, यदि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, तो अपनी बात रखना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में युवाओं की आवाज दबनी नहीं चाहिए। प्रश्न आंदोलन करने का नहीं है, प्रश्न यह है कि आंदोलन की दिशा किसके हाथ में है। इतिहास गवाह है कि अनेक बार वास्तविक पीड़ा किसी और की राजनीति का मंच बन गई। जिन युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी समस्या पीछे छूट गई और बहस किसी दूसरे विषय पर पहुंच गई। मुद्दा वही रहा, लेकिन मंच पर चेहरे बदल गए, नारे बदल गए और उद्देश्य भी बदल गया। यही वह क्षण होता है, जब आंदोलन अपने मूल लक्ष्य से भटकने लगता है। आज की जेन-जी तकनीक को समझती है, जानकारी तक उसकी पहुंच पहले की किसी भी पीढ़ी से अधिक है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यही शक्ति तब कमजोरी बन जाती है, जब सोशल मीडिया की तेज रफ्तार, भावनात्मक भाषण, वायरल वीडियो और प्रभावशाली चेहरे उसकी स्वतंत्र सोच पर हावी होने लगते हैं। याद रखिए, किसी आंदोलन में शामिल होना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे-समझे किसी के पीछे चल पड़ना खतरनाक हो सकता है। हर नारा आपका नहीं होता, हर भाषण आपके हित में नहीं होता और हर मंच आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहता। इसलिए स्वयं से कुछ प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या जो लोग आपके साथ खड़े हैं, वे आपकी समस्या का समाधान चाहते हैं या केवल आपकी संख्या का उपयोग करना चाहते हैं? क्या आंदोलन का एजेंडा वही है, जिससे आप जुड़े थे, या वह धीरे-धीरे किसी और दिशा में मुड़ चुका है? क्या निर्णय आंदोलन से जुड़े युवाओं द्वारा लिए जा रहे हैं, या कोई दूसरा उसकी दिशा तय कर रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर ही तय करेंगे कि आप आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं या केवल भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। लोकतंत्र में आवाज उठाना अधिकार है, लेकिन विवेक बनाए रखना जिम्मेदारी है। अधिकार और जिम्मेदारी साथ-साथ चलें, तभी परिवर्तन सकारात्मक होता है। यदि विवेक खो गया, तो सबसे सशक्त आंदोलन भी किसी और के हाथ का औजार बन सकता है। जेन-जी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपनी बात पूरी मजबूती से कहनी चाहिए। उसे अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। उसे व्यवस्था से जवाब भी मांगना चाहिए। लेकिन उतनी ही दृढ़ता से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी आवाज किसी और की महत्वाकांक्षा का माध्यम न बन जाए। याद रखिए, कठपुतली कभी अपनी दिशा स्वयं तय नहीं करती। उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। लेकिन जागरूक युवा कठपुतली नहीं बनते, वे अपनी डोर स्वयं थामते हैं। इसलिए आवश्यकता आंदोलन से दूर रहने की नहीं, बल्कि आंदोलन के प्रति जागरूक रहने की है। आवश्यकता अपनी आवाज दबाने की नहीं, बल्कि अपनी आवाज पर अपना अधिकार बनाए रखने की है। आवश्यकता भीड़ बढ़ाने की नहीं, बल्कि उद्देश्य बचाए रखने की है। यदि जेन-जी यह अंतर समझ गई, तो कोई भी उसकी ऊर्जा, उसके उत्साह और उसके भविष्य का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर पाएगा।

थ्रेडिंग के बाद पिंपल्स से छुटकारा...



आजकल ज्यादातर महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे से अनचाहे बालों को हटाने के लिए थ्रेडिंग करवाती हैं। हर तरह की त्वचा पर थ्रेडिंग हो सकती है फिर चाहें आपकी त्वचा संवदेनशील हो या नहीं। पर अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर महिलाओं को थ्रेडिंग करवाने के बाद में दाने, पिंपल्स हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको थ्रेडिंग के बाद होने वाले पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से टिप्स देगें। थ्रेडिंग करवाने से पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धों लें। ऐसा करने से थ्रेडिंग के समय दर्द कम होता है। चेहरे को कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से पोंछ न कि रगड़कर पोंछें। अगर आप रगड़ कर कर पोंछेगे तो त्वचा ड्राई हो जाती है। अगर आपने घर पर ही टोनर बनाया हुआ है तो उसे चेहरे को हल्का नम कर दें। अगर आपके चेहरे पर दाने निकले हुए है तो उन पर जड़ी बूटी से बना टोनर ही लगाएं या फिर घर में बनी दालचीनी की चाय को टोनर के रूप में लगा सकती हैं। यह सब करने के बाद ही आप पार्लर में जाकर थ्रेडिंग करवाएं। जलन और संक्रमण से बचने के लिए अपनी आईब्रो पर बर्फ लगाएं। चेहरे को हमेशा गुलाब जल से ही धोएं। इसे लगाने से आपकी आईब्रो पर लगे कट, दाने व पिंपल ठीक हो जाते है। ध्यान में रखें कि आप जब भी थ्रेडिंग करवाकर आए तो थ्रेड़िंग वाले हिस्से को न छुएं। थ्रेडिंग करवाने के बाद कम से कम 12 घंटे की अवधि के दौरान एसिड की मौजूदगी वाले सुगांधित कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे क्लींजर और मॉश्चराइजर न लगाएं। थ्रेडिंग के बाद किसी तरह का स्टीम ट्रीटमेंट कभी न करवाएं।

वह अजीब सा नंबर...



आप टीवी पर अपना कोई पसंदीदा शो देख रहे हैं और अचानक एक नीली पट्टी में अजीब सा नंबर दिखने लग जाता है। यह नंबर कभी-कभी आपको इरिटेट करता है, क्योंकि शो के दौरान कई बार ये दिखने लग जाता है। लेकिन क्या आपको इस नंबर की कहानी पता है? अचानक दिखने वाला यह नंबर बहुत काम का होता है और यही नंबर वीडियो पाइरेसी से भी बचाता है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली रेंडम नंबर की स्ट्रिप को क्षेत्र के आधार पर चैनल एल्गोरिथम के जरिए जनरेट करता है। यह नंबर किसी भी शो के वीडियो के बीच में रेंडम तरीके से रिफ्लेक्ट होता रहता है, ताकि इस वीडियो का कोई दूसरा इस्तेमाल या कॉपी न कर पाए। अगर कोई टीवी के किसी शो या सीरियल के वीडियो को कैमरा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिवाइस के माध्यम से रिकॉर्ड करता है, तो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा नंबर भी उसमें आ जाता है। इससे इस बात का पता लगाने में आसानी हो जाती है कि किस क्षेत्र में टीवी के सीरियल्स और शो को कॉपी किया गया है। नंबर स्ट्रिप के जरिए ही मीडिया कंपनीज बेहद आसानी से उस जगह को ट्रैक कर लेती हैं, जहां बैठकर किसी टीवी शो रिकॉर्ड किया गया होता है। इसके बाद उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होती जो पाइरेटिड कंटेट के लिए जिम्मेदार होता है।

घड़ियों का यह राज...



चाहे वो रोलेक्स घड़ी हो या टाइटन सबके विज्ञापन में हमेशा समय 10.10 ही होता है पर क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है। यह कोई संयोग नहीं है इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कारण हैं। अगर देखा जाए तो इस समय घड़ी की सूइयां जिस आकार में होती है वो हंसने की आकृति बनाती हैं जो एक बहुत ही सकारात्मक चिन्ह होता है। इससे पहले विज्ञापनों में 8.10 का समय इस्तेमाल किया जाता था मगर इस समय से जो आकृति बनती थी उसका मनोवैज्ञानिक असर गलत पड़ता था। कई कारणों में से एक कारण यह भी है की यह समय प्रथम दृष्टि में दिख जाता है ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इस समय की वजह से ब्रांड नाम और घड़ी की अन्य विशेषताएं भी आसानी से दिख जाती है। एक और बात ध्यान देने योग्य है की इस समय के दौरान सेकेंड वाले कांटे को 35 सेकेंड पर रोक दिया जाता है। इसको इस तरह भी माना जाता है की यह आकृति वी आकर बनाती है जिसे जीत का आकार भी माना जाता है।

स्मार्टफोन के स्क्रैचेस से छुटकारा...?



अगर आपके स्मार्टफोन पर जरा सी भी खरोंच आ जाए तो आपको बहुत बुरा लगता होगा पर अब आपको किसी भी चीज का बुरा मानने की जरूरत नहीं ही क्योंकि अब आप अपनी स्क्रैच्ड स्क्रीन को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आपके फोन के स्क्रैच को ठीक कर सकता है। दो चम्मच बेकिंग सोडा में एक चम्मच पानी डालें और एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। एक सूखे कपड़े में इस पेस्ट को लगा कर आराम से स्क्रीन पर घुमाइए और फिर देखिए कमाल। अपने स्क्रीन के स्क्रैच को ठीक करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर हल्के हाथ से टूथपेस्ट रगड़ें और चुटकियों में आपकी स्क्रीन से स्क्रैचेस गायब हो जाएंगे। फोन की स्क्रीन टूट गई है तो क्रैक लाइन्स पर ट्रांसपैरेंट नेल पॉलिश लगाएं और थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन फिक्स हो जाएगी। सैंडपेपर का इस्तेमाल आपको फोन से स्क्रैच से छुटकारा दिला सकता है। अच्छी क्वॉलिटी का सैंडपेपर अपने फोन की स्क्रीन पर हल्के हाथ से रगड़ें कुछ ही देर में सारे स्क्रैचेस गायब हो जाएंगे।



पहाड़ों पर बाइक की सवारी...



चेहरे से टकराती, बालों को सहलाती तेज हवा, कभी तेज चढ़ाई, कभी तीखी ढलान, बल खाती सड़क, गहरे मोड़, चारों ओर हरियाली, पौधों की सुगंध किसी का भी मन मोहने में सक्षम है। यही वह आकर्षण है जिसमें बंधे लोग बार-बार पहाड़ों की ओर मोटरसाइकिलें लेकर निकल पड़ते हैं।

एडवेंचर युवाओं का आज सबसे बड़ा पैशन है। एडवेंचर टूर पर जाना और वहां के हालातों से रूबरू होकर वापस लौटना जिंदगी भर के लिए आपकी यादों में बस जाता है। बलखाती सड़क, गहरे मोड़ , तीखी ढलान के मोह में युवा बार-बार पहाड़ों की तरफ मोटरसाइकिलें लेकर निकल पड़ते हैं।

मोटरसाइकिल की सवारी में वैसे तो रोमांच ही रोमांच है, लेकिन पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है। यह बात जरूर है कि इसमें खतरे भी कम नहीं हैं। दरअसल, पहाड़ों पर ले जाने वाली मोटरसाइकल शक्तिशाली होनी चाहिए, भले ही उसकी स्पीड ज्यादा न हो, लेकिन बैलेंस करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ऐसी यात्रा से पहले कुछ तैयारी भी करनी होती है। पहाड़ की यात्रा में बैलेंस भी सबसे जरूरी है। ऐसी बाइक जिसका वजन आगे-पीछे 40-60 हो, वो बेहतर है। आपको बाइक में होने वाली छोटी-मोटी गड़बडी ठीक करना आनी चाहिए। बेहतर रोड ट्रिप के लिए चौड़ा टायर सही होता है।

गाड़ी का टूपिन ज्यादा पॉवरफुल होना जरूरी नहीं, लेकिन उससे शक्ति कम आरपीएम पर मिल सके तो ठीक होता है। आजकल मोटरसाइकिल अपनी निर्माण गुणवत्ता के चलते काफी विश्वसनीय होने लगी है। बाजार में हर व्यक्ति की जरूरत के अनुरूप मोटरसाइकिलें हैं। 100 सीसी से लेकर 350 सीसी तक मोटरसाइकिलें आम हैं और विशेष मोटरसाइकिलें विदेश से मंगाना भी कठिन नहीं।

सर्विसिंग करा लें

आप जो बाइक ले जाना चाहें उसकी सर्विसिंग जरूर करा लें, भले ही वह ठीक चल रही हो। पहाड़ी रास्ते प्रायः बारिश या भूस्खलन के चलते खराब होते रहते हैं। अतः मोटरसाइकिल के नट-वोल्ट की जांच ठीक से कर लें। मोटरसाइकिल में सबसे बड़ी समस्या पंक्चर की होती है। अतः इसकी व्यवस्था जरूरी है। आपको छोटी-मोटी गड़बड़ी ठीक करना, पहिया खोलना, टयूब निकालना, पंक्चर लगाना आना चाहिए। वैसे अब पहाड़ों में लोगों की आवाजाही बढ़ने से जगह-जगह पंक्चर ठीक करने वाले भी मिलने लगे हैं, परंतु बीच राह में आप ही अपने मददगार होंगे। यात्रा के दौरान अपनी मोटरसाइकिल को प्रतिदिन सुबह टायरों में हवा, सभी नट-वोल्ट, इंजन ऑयल तथा स्टार्टिंग हेतु जांचना चाहिए। सामान बांधते समय भी मोटरसाइकिल के संतुलन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्पेयर्स में प्लग, स्टार्टिंग क्वायल, क्लच वायर, ब्रेक वायर, पंचर किट, फुट पंप, हेडलाइट बल्ब, चेन लिंक, क्लच तथा ब्रेकलीवर, रबर पाइप और स्पेयर ट्यूब्स आदि जरूर रखें। टूल्स में प्लग ओपनर, स्क्रू ड्राइवर, रिंच, टायर ओपनर लीवर्स, प्लास, फोल्डिंग हैमर, स्टार्टिंग क्वायल खोलने लगाने के औजार, वाल्व ओपनर, एक छोटी व शक्तिशाली टॉर्च भी रखें।



सामान कम रखें

मोटरसाइकिल यात्रा में सामान कम से कम होना चाहिए। फिर भी जैकेट, विंडचीटर, जींस, मौसम के अनुरूप जूते, मोटे मोजे, ग्लव्स, मफलर, धूप का चश्मा, छोटे बैग्स, हैवरसैक वाटर बॉटल जरूर रखें। सामान को बांधने के लिए सूती रस्सी का प्रयोग करें और उसे पॉलीथिन से ढक कर रखें।

लगातार न चलें

पहाड़ों पर कभी भी लगातार लंबी दूरी तय न करें। बीच-बीच में रुकना साइटसीइंग के साथ एकरसता तोड़ने तथा थकान से बचने हेतु भी जरूरी हैं। पहाड़ पर कभी भी तेज गति से बाइक नहीं चलानी चाहिए। अंधेरा होने पर पहाड़ों पर नहीं चलना चाहिए। यात्रा में दूरी के हिसाब से पहले से योजना बना कर एक दिन में तय हो सकने वाली दूरी का लक्ष्य रखना चाहिए। साथ ही ठहरने के स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए।

क्षेत्र की जानकारी जरूरी

यात्रा पर निकलने से पहले आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां के वातावरण, रास्ते, सड़कें, रुकने के स्थान, दर्शनीय स्थल, विशेषताएं, जाने का सही समय आदि सभी जरूरी जानकारियों से लैस हो लें। आप को हमेशा ही अपने पैर अपनी ब्रेक पर रखने चाहिए क्योंकि न जाने कब इसकी जरूरत पर जाए। इससे आप अपनी मोटर साइकिल की स्पीड कम कर सकते हैं। याद रक्खें कभी भी इसकी गलती न करे। वरना बाइक किसी से ठुक जाएगी।

रोड पर ध्यान रखें

पहाड़ का रोड हमेशा ही छोटा होता है क्योकि यह पहाड़ को काट कर बनाया जाता है। आप यहां लापरवाह नहीं हो सकते हैं। एक बार गलती होने पर यहां किसी भी तरह बचा नहीं जा सकता। आप को पूरी तरह अपना ध्यान रोड की तरफ केंद्रित करना होगा। आपको यह देखना होगा कि कौन आगे से आ रहा है। आपको उसके मुताबिक मोटर साइकिल को चलाना होगा। यहां रास्ते सांप की तरह होते हैं। जरा भी ध्यान भंग दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। उपयोग में केवल दूसरा व तीसरा गियर ही लाएं। वरना आप की बाइक रुक सकती है और पीछे जाम लग सकता है।



संतुलन है जरूरी

ऐसी यात्रा से पूर्व कुछ तैयारियां भी करनी होती हैं, जिससे विपरीत हालात बनने पर उनसे आसानी से निबटा जा सके। पहाड़ की यात्रा में संतुलन सबसे जरूरी है। टायर की चौड़ाई वाहन के रोड ग्रिप को तय करती है। बेहतर रोड ग्रिप के लिए चौड़ा टायर सही होता है। गाड़ी का टूपिन अधिक ताकतवर होना जरूरी नहीं, पर उससे शक्ति कम आरपीएम पर मिल सके तो ठीक होता है। ऐसी बाइक पहाड़ों पर अधिक उपयोगी होती है, जिसके दूसरे व तीसरे गियर में न सिर्फ पर्याप्त शक्ति हो, बल्कि उन्हें बार-बार बदलने की जरूरत न पड़े। यद्यपि जब रोमांचक यात्रा पर हों तो ईधन खपत खास महत्व नहीं रखता, पर सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में कम ईधन खपत वाली बाइक आपको चिंतामुक्त रखेगी।



मोड़ते समय याद रखें

जैसे ही मोड़ आए तो आप को एक दम ही किसी दूसरी गाड़ी को क्रॉस नहीं करें क्योंकि सामने से कोई आ सकता है मोड़ होने की वजह से वह आप को दिखाई नही देगा। इस कारण मोटरसाइकिल उससे ठुक सकती है। अपनी बाइक की गति 20 किमी / घंटा या 30 किमी / घंटा पर ही रखें। छोटी दूरी के बाद रोड बदल जाता है स्पीड यदि ज्यादा होगी तो आपको रोकना मुश्किल होगा जिससे दुर्घटना हो सकती है। आप को खुद पर भरोसा रखना होगा कि आप में मोटर साइकिल को पहाड़ पर चलाने की शक्ति है। आप में ऐसा साहस है कि आप इस काम को आसानी सी कर सकते हैं। आपको कोई ताकत भयभीत नहीं कर सकती है। यह सच है कि पहाड़ पर जोखिम तो है पर आप हर जोखिम लेने के लिए सक्षम हैं।

कार से रोड ट्रिप...

यदि आप कार से रोड ट्रिप पर जाने का सोच रहे हैं तो अपनी कार में जरूरत के अनुसार चीजें ले जाना न भूलें। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीजें जो हमेशा आपकी कार में होनी चाहिए।

विंडस्क्रीन माउंट

आपको चाहे अब तक विंडस्क्रीन माउंट जरूरत महसूस नहीं हुई हो लेकिन एक बार इसका इस्तेमाल करने से आपको इस बात का अहसास होगा कि यह आपके लिए कितना जरूरी है। इसके इस्तेमाल से आपका फोन हमेशा सेफ बना रहेगा फिर चाहे आपको ब्रेकर से होकर गुजरना पड़े या गड्ढों से, आपके फोन को कोई नुकसान नहीं होगा। विंडस्क्रीन माउंट की मदद से फोन को इस्तेमाल करना भी बेहद आसान हो फिर चाहे आपको मैप का इस्तेमाल करना हो या फोन में गाने सुनने हों।



कार सेफ्टी हैमर

मुसीबतें बता कर नहीं आती, इसलिए आपको सेफ्टी से जुड़ी चीजें भी अपनी कार में रखनी चाहिए। अपनी कार में आपको सेफ्टी हैमर रखना चाहिए जिससे कोई भी मुसीबत आने पर आप आराम से कार का शीशा तोड़ कर बाहर निकल सकें साथ ही इसमें बने कटर से आप सीट बेल्ट को भी आसानी से काट सकते हैं।



टॉर्च

हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में फ्लैशलाइट फीचर हो लेकिन हर जगह उसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। हो सकता है जिस समय आपको टॉर्च की जरूरत हो उस समय आपके फोन की बैटरी लो हो और कुछ ही समय में वो आपको परेशानी में छोड़ कर बंद हो जाए, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कार में एक टॉर्च हमेशा रखें।

खाली कैन

अगर कभी आपकी कार में रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए और ऐसा कोई तरीका नहीं हो कि आप अपनी कार को किसी तरह पेट्रोल पंप तक ले जाएं तो ऐसे समय में केवल यह कैन ही आपकी मदद कर सकता है। ऐसे समय में अपनी कार को लॉक कर, ऑटो रिक्शा लेकर पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल ले कर वापस आएं और अब आप कार से वहां जा सकते हैं जहां आप जा रहे थे।

एयर कंप्रेसर पंप

एयर कंप्रेसर बाजार में अलग- अलग डिजाइन में मौजूद हैं और यह आपके लिए बेहद जरूरी भी हैं। इलेक्ट्रिक मॉडल मकेनिकल मॉडल से बेहतर ऑपशन है। ध्यान रखें कि इसकी तार इतनी लंबी हो कि आप सभी टायर्स में इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें।



मैटेलिक कलर्स का क्रेज...



कुछ ट्रैंड्स और स्टाइल ऐसे होते हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। हम जब चाहे इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और भीड़ में भी सबसे अलग लग सकते हैं। फैशन से कभी भी आउट न होने वाले कलर्स में मैटेलिक कलर्स भी शामिल हैं। इनका टैक्सचर यानी शाइनी और डल फिनिश आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकती हैं। हर पैटर्न की ड्रैस इन कलर्स में खिल उठती है। आपको किसी पार्टी में जाना हो और आप डिफरेंट दिखना चाहती हैं तो मैटेलिक ड्रैस एकदम परफैक्ट है।

वनपीस ड्रैसेस और गाउन





मैटेलिक टच में वनपीस ड्रैसेस और गाउन इन दिनों हॉटैस्ट फैशन ट्रैंड बने हुए हैं। फैशन डिजाइनर्स का कहना है कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ग्रे जैसे मैटेलिक कलर्स में ड्रैसेस विंटर सीजन में ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। पैंट्स से लेकर स्कर्ट्स तक में इन्हीं कलर्स का यूज किया जा रहा है। मैटेलिक का मतलब यह नहीं है कि वो बहुत ग्लिटरी ही हों। आप ऐसी ड्रैसेस भी सलेक्ट कर सकती हैं जो मैटेलिक तो हों पर डल फिनिश में हों। इन्हें दिन में भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। इनके साथ ग्लिटरिंग जरूर कैरी की जा सकती हैं।

मैटेलिक गाउन

बिना किसी डिटेलिंग के प्लेन मैटेलिक शाइन गाउन के साथ सिंपल, सोबर और स्टाइलिश दिखा जा सकता है। डिटेलिंग के साथ फ्रंट स्लिट वन ऑफ शॉल्डर गाउन आपको ग्लैमरस और सैक्सी लुक देगा। सिल्वर कलर पर सिल्वर और डल गोल्ड एम्ब्राइड़ी, गाउन के लुक को और भी आकर्षक बना देगी। मैटेलिक गाउन के साथ सिर्फ ईयररिंग्स कैरी करना ही सफिशिएंट होगा।

लाइनिंग वनपीस

मैटेलिक लुक के साथ लाइनिंग वनपीस ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। मैटेलिक सिल्वर और गोल्डन वनपीस ड्रैसेस के साथ चेस्टफील्ड कोट और हंटर कोट का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया लगता है। इसके साथ सिर्फ लाइट वेट ज्वैलरी कैरी करना सफिशिएंट रहेगा।

एक्सेसरीज भी

अपने लुक को ग्लैमराइज करने के लिए सिर्फ ड्रैसेस ही नहीं बल्कि मैटेलिक कलर की बैल्ट्स, ज्वैलरी, हैंडबैग्स और यहां तक कि शूज भी सेलेक्ट कर सकती हैं। मैटेलिक कलर के आउटफिट्स को हमेशा न्यूट्रल शेड्स जैसे बेज, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक के साथ टीमअप करें और एक्सेसरी भी न्यूट्रल कलर की ही कैरी करें। नाइट आउट के लिए ब्लैक, ब्लू या दूसरे डार्क शेड्स सलेक्ट कर सकती हैं। बहुत ज्यादा शाइन आपको ओवरशाइनी दिखा सकता है, लेकिन एक बैलेंस्ड शाइन से आप सैंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकती हैं। मैटेलिक आउटफिट्स के साथ मेकअप को भी कम से कम ही रखने की कोशिश करें।



सावधानी जरूरी

मैटेलिक कलर्स के साथ थोड़ा केयरफुली प्ले करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपसे थोड़ी-सी भी गलती हो गई तो ये ट्रैंड आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर भी साबित हो सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप किसी भी तरह की मिस्टेक से आसानी से बच सकती हैं। खुद को मैटेलिक कलर्स से कवर करने की गलती कभी ना करें। टॉप और बॉटम में से किसी एक को ही इस फैब्रिक में पिक करें। टॉप अगर मैटेलिक हो तो अपने ट्राउजर्स या स्कर्ट्स को प्लेन रखें। गोल्ड और ब्राउन या ब्लैक कलर की मैसी शेड्स स्कर्ट के साथ प्लेन ब्लैक या ब्राउन सैंडो टॉप काफी फबती है। अगर बॉटम मैटेलिक कलर्स में है तो लाइट ज्वैलरी ही कैरी करनी चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सपा पर बरसे अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि पेपर लीक आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है. इसका शिकार युवा होता है. इस बीमारी का इलाज हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे. हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में मिली है. हर जख्म का इलाज मोदी सरकार ने ही किया है. आतंकवाद-नक्सलवाद को जड़ से खतम करने का काम भी हमने ही किया है. हमारी सरकार युवाओं के साथ है और यह किया है कि ऐसा कानून लाएंगे, जो सख्त होगा. आज का यह कानून आप देखिए. 2024 के कानून में संशोधन करने के लिए लाए हैं. हम सिस्टम को और फुलप्रूफ करना चाहते हैं. तारीख पर तारीख न हो, इसके लिए सिस्टम बनाने जा रहे हैं. आप तो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे, सदन चलने नहीं दे रहे थे. राहुल गांधी को लगा कि युवाओं ने पूछा नहीं, अखिलेश जी के साथ जाकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर लेट गए. आपकी तड़प समझ रहा हूं, अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिलने वाला है. नीट एग्जाम में जैसे ही लीक जैसा कुछ होने की खबर आई, हमारी सरकार ने तीन दिन में फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया. 40 हजार से ज्यादा सेंटर पर कराया।



देव आनंद के बेटे का हार्ट अटैक से निधन

नई दिल्ली। बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार दिवंगत देव आनंद के परिवार से एक बुरी खबर सामने आई है. उनके बेटे सुनील आनंद अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने 70 की उम्र में अपनी अंतिम सांस लंदन में ली. उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उनका निधन हुआ. ये जानकारी उनके परिवार के सदस्य ने दी. देव आनंद की पोती जीना नारंग ने सुनील आनंद के निधन की बात कंफर्म करते हुए एक स्टेटमेंट भी जारी किया. उन्होंने कहा कि भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के निधन पर शोक व्यक्त करता है. इस मुश्किल समय में हमें जो प्यार, दुआएं और साथ मिला है, उसके लिए हम सभी के आभारी हैं. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस कठिन समय में हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें.देव आनंद के बेटे सुनील आनंद भी एक्टिंग कर चुके थे. बॉलीवुड लेजेंड ने खुद अपने बेटे को फिल्मों में लॉन्च किया था. साल 1984 में फिल्म आनंद और आनंद से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा।



दोबारा प्रदर्शन करेगी सीजेपी

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर दिए गए अंतरिम आदेश पर सीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया तो वो फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे. अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर पुलिस के हाथों स्टूडेंट्स को परेशान करना जारी रहा, तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी. सरकार को स्टूडेंट्स को टारगेट करना और उन पर विच-हंटिंग बंद करनी चाहिए। नेता सौरव दास ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने छात्रों से किया गया अपना वादा तोड़ा, तो उनके पास देशव्यापी आंदोलन दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. सौरव दास ने अपने बयान में कहा कि सीजेपी सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के पारित अंतरिम आदेश, खासतौर पर निर्देश संख्या 4, पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है।

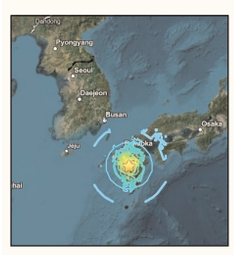


पीओके में पहले चरण के नतीजों पर विवाद

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 45 विधानसभा सीटों के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक तीन चरणों में मतदान हो रहा है. पहले चरण के नतीजों में 13 सीटों में से सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने 9 और पीपीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. केंद्र में दोनों दल गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सात सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए जांच पूरी होने तक नतीजे घोषित नहीं करने की मांग की. पार्टी नेता नैयर बुखारी ने कहा कि उनकी जीती हुई सीटें पीएमएल-एन को दे दी गईं. वहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया. हालांकि, मतदान के दिन हुई हिंसा मे पीपीपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए. चुनाव से पहले विवादित 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी थे।



जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप



नई दिल्ली। जापान के क्यूशू द्वीप पर मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. यह भूकंप कुमामोतो क्षेत्र में आया और इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, भूकंप के बाद 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है. जापान सरकार ने कुमामोतो के अलावा नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाजाकी प्रान्तों में भी आपातकालीन भूकंप चेतावनी जारी की है. ये सभी इलाके क्यूशू द्वीप पर स्थित हैं. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है. स्थानीय प्रशासन भूकंप से हुए असर का आकलन कर रहा है और साथ ही सुनामी के खतरे पर भी लगातार नजर बनाए हुए है. आपातकालीन टीमें अलर्ट पर हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

राहुल गांधी के भाषण में 'अंधभक्त' शब्द पर बवाल

हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने कहा - बिल पर बोलें, संसदीय कार्य मंत्री ने किया हस्तक्षेप

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने एक छात्रा से हुई बातचीत का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने छात्र, मूर्ख और अंधभक्त तीन श्रेणियां बताईं। राहुल गांधी ने कहा, मैंने कहा कि अंधभक्त की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि अंधभक्त वह है जो मान लेता है कि यह बड़ी छवि वाला बेवकूफ ही भगवान है। इसके बाद कुछ देर तक लोकसभा में हंगामा मच गया।

राहुल गांधी ने एक छात्रा से बातचीत का जिक्र किया, जिसने उन्हें तीन तरह के लोगों की कैटगरी बताई। राहुल गांधी ने कहा, पहली तरह के छात्र सच को गर्व से स्वीकार करते हैं। मैंने पूछा कि दूसरे तरह के व्यक्ति के बारे में क्या? उसने कहा कि दूसरे तरह के व्यक्ति को एक छवि की जरूरत होती है। उसे एक छवि बनानी पड़ती है और क्योंकि वह छवि सच नहीं होती, तो एक बेवकूफ खुद को भगवान दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए उसे एक बड़ी छवि बनानी पड़ती है। मैंने उससे पूछा कि तीसरी श्रेणी कहां आती है? वह श्रेणी अंधभक्त की है। उसने कहा, अंधभक्त वह व्यक्ति होता है, जो पूरी तरह यकीन कर लेता है कि कोई दूसरा बेवकूफ भगवान है।

उन्होंने आगे कहा, तो तीन वर्ग के लोग हैं। एक वर्ग है विद्यार्थी का, जो विद्या का अर्थ है। बाकी दो वर्ग का मैं नाम नहीं लूंगा। छात्र इन दोनों से नहीं डरता। वह किसी पर हमलावर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका सच दूसरे के सच से अलग होगा। दूसरे वर्ग को हिंसा की जरूरत होती है, दबाव बनाने की जरूरत होती है।



इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, अगर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। मेरा मानना है कि वह एक छात्र के नाम पर उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में उस शब्द का इस्तेमाल वही कर रहे हैं। वह असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कई लोगों को लगता है कि छात्रों को पेपर लीक की वजह से गुस्सा आया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले ही क्रूर है। लाखों रुपये गरीबों से लिए जाते हैं। हर चीज प्राइवेटाइज है। पेपर लीक, एक परीक्षा में कुछ होता है, दूसरे में कुछ। एक में रिएग्जाम होता है, दूसरे में नहीं होता है। यह एक बेहद खराब व्यवस्था है। यह सिस्टम और इसकी आत्मा को कब्जे में कर लिया गया है। इसे आरएसएस ने कब्जे में किया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम यूपीए नहीं है, हमारे मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देते। वो सही कह रहे हैं। यहां जो हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कभी नहीं चलाते। उसे आरएसएस चलाता है। मंत्री के दफ्तर में बैठा एक ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी)। छात्रों को कुछ बोलने नहीं दिया जाता। उन्हें अपने मन की चीज फॉलो नहीं करने दी जाती। उन्हें वह इतिहास पढ़ना पडता है, जो आरएसएस लाना चाहता है। हर यूनिवर्सिटी में आज आरएसएस से जुड़ा वाइस चांसलर है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक व्यक्ति हैं, आपका असली दुश्मन आरएसएस है।

छात्रों के हालिया प्रदर्शनों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं देश के भविष्य की आवाज को देखकर बहुत उत्साहित और आश्वस्त हुआ। सड़कों पर जो हुआ, वह आक्रोश, हिंसा या नफरत नहीं थी। यह देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ी की गहरी भावना की अभिव्यक्ति थी। मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक दलों को इस भावना का सम्मान करना चाहिए, जिसमें मेरे भाजपा के मित्र भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर भाजपा के मेरे मित्र अपने बच्चों से पूछेंगे कि वे अपने भाई-बहनों के इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों में भी समर्थन दिखाई देगा। जो कुछ हुआ, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए।

राहुल ने शाह पर लगाया गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में उनका सामना करने से डरते हैं। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि शाह ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था और उन पर उनके खून में छर्रे उतारने का आरोप लगाया। इन टिप्पणियों का सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री के खिलाफ गांधी के आरोपों के आधार और सबूत पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तथाकथित गृह मंत्री में संसद में आकर बैठने की हिम्मत नहीं है। इन बच्चों के माता-पिता में भाजपा-आरएसएस का सामना करने की हिम्मत नहीं थी; फिर भी बच्चे वहां डटे रहे और उन पर जो कुछ भी फेंका गया, उसका सामना किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद न होने पर तंज कसते हुए गांधी ने कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तथाकथित गृह मंत्री में लोकसभा में आकर बैठने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें वह आदेश पेश करने की चुनौती दी और कहा हमें वह आदेश दिखाएं। स्पीकर ने भी राहुल की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियों को तब तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता, जब तक कि उनके दावों का कोई तथ्यात्मक आधार न हो। बिरला ने राहुल से तथ्यों पर बात करने को कहा। बिरला ने गांधी को याद दिलाया कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनसे तथ्यों पर बात करने और बिल पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद की जाती है।

अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर रिजिजू ने जताई आपत्ति

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दखल देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर संसदीय मर्यादा में रहते हुए राहुल गांधी को बात करनी है। हम बात सुनने को तैयार हैं। रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी ने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सत्तापक्ष के सदस्य उत्तेजित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, आपको (राहुल गांधी) पता है कि असंसदीय शब्दों को लेकर नियम हमने नहीं बनाए हैं। नियमों के मुताबिक संसदीय मर्यादा में रहते हुए आपको बात करनी है तो हम आपकी बात सुन रहे हैं। बार-बार आपने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया। हमने आपके भाषण को बाधित नहीं करना चाहा। हमारा यही कहना है कि आप असंसदीय शब्द का इस्तेमाल न करें। उन्होंने राहुल गांधी से अनुरोध करते हुए कहा, आप विपक्ष के नेता हैं। आप ऐसे परिस्थिति खराब न करें। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया है।

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर राज्यसभा में बवाल!

जेपी नड्डा- मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़े



नई दिल्ली। बुधवार को राज्यसभा में तब हंगामा मच गया जब सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पिछले हफ़्ते संसद तक छात्रों के विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जवाब दिया। उन्होंने इसे सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति बताया और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और इसे सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस अत्याचार का मुद्दा उठाया और इस कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की।

खड़गे ने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों पर हमला किया, वे आज़ाद घूम रहे हैं। उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी उनका साथ दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की, साथ ही कार्रवाई का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की मांग की। नड्डा, जिन्होंने जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर केंद्र की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की विपक्ष की मांग का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई की। नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत सामान्य स्थिति थी, जिसे हमें समझना होगा। पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। उन्होंने आगे कहा कि जो भी छात्र एक्टिविज़्म (सक्रियता) से जुड़ा है, उसे ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। अपने अनुभव का ज़िक्र करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने याद किया कि कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान छात्र एक्टिविज़्म के दिनों में उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया था।

उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान छात्र आंदोलन में मुझे भी गिरफ़्तार किया गया था। किसी भी छात्र कार्यकर्ता को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह बहुत सामान्य बात है। घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा, वे इसे सनसनीखेज बना रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 90 रन से हराया

त्रिनिदाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। टेस्ट कप्तान के तौर पर बाबर आजम की वापसी भी टीम की किस्मत नहीं बदल सकी और वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए पहले टेस्ट में 90 रन से शानदार जीत दर्ज की। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 120 रन पर सिमट गई।



चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन बनाने थे, लेकिन शुरुआत से ही बल्लेबाज दबाव में दिखे। कप्तान बाबर आजम ने नाबाद अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। पूरी टीम 120 रन पर ऑलआउट हो गई और पाकिस्तान को 90 रन से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज की जीत के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज जयडेन सील्स रहे। उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके और पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर मेजबान टीम ने मैच पर पूरी पकड़ बनाए रखी।

चौथे दिन वेस्टइंडीज ने 126/7 से आगे खेलना शुरू किया। शमार जोसेफ ने 27 गेंदों में 38 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें एक चौका और चार छक्के शामिल रहे। उन्होंने केमर रोच (18) के साथ 61 रन की अहम साझेदारी की। मोहम्मद अब्बास ने पांच विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 181 रन पर समेट दिया, लेकिन तब तक मेजबान टीम पाकिस्तान के सामने 211 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख चुकी थी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स को पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, सर गारफील्ड सोबर्स की जयंती के दिन मिली यह जीत वेस्टइंडीज के लिए और भी खास बन गई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 889 अंक उछला निफ्टी 24,251 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को शानदार तेजी देखने को मिली। आईटी, एफएमसीजी और मेटल शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते सेंसेक्स 889 अंक यानी 1.16 फीसदी बढ़कर 77,654.60 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी 265 अंक यानी 1.10 फीसदी की बढ़त के साथ 24,250.20 के स्तर पर बंद हुआ। बड़े शेयरों के साथ-साथ व्यापक बाजार में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 0.82 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 1.48 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। इससे साफ है कि निवेशकों की दिलचस्पी केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही। निफ्टी 50 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंफोसिस सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर रहे। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल और निफ्टी एफएमसीजी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंकों ने वसूले 7000 करोड़ से ज्यादा

नईदिल्ली। सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपने ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर 7,086.63 करोड़ रुपए पेनल्टी के तौर पर वसूल डाले। सरकार ने संसद में दी जानकारी में बताया कि वित्तवर्ष 2025-26 में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने की वजह से ग्राहकों से 4,948.71 करोड़ रुपए वसूले। यह चार्ज सेविंग और करेंट अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने की वजह से लगाया गया है। सरकारी बैंकों ने भी इस दौरान जमकर वसूली की है और अपने ग्राहकों से 2,137.92 करोड़ रुपए वसूले। राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने आरबीआई के आंकड़ों का हवाल देते हुए कहा कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर सबसे ज्यादा वसूली एचडीएफसी बैंक ने की है। एचडीएफसी बैंक ने पिछले वित्तवर्ष (2025-26) में ग्राहकों से कुल 1,798.14 करोड़ रुपए वसूले।

एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने जुटाया करोड़ों का वित्तपोषण

नई दिल्ली। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने अपनी 250 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से 3,404.57 करोड़ रुपए का वित्तपोषण हासिल किया है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि इस राशि का इस्तेमाल एसीएमई ऊर्जा वन (तृतीय चरण) परियोजना के विकास एवं निर्माण में किया जाएगा। यह परियोजना राजस्थान के जैसलमेर स्थित फतेहगढ़ (द्वितीय) और गुजरात के देवभूमि द्वारका स्थित जामखंभालिया में फैली हुई है। बयान के अनुसार, इस परियोजना के लिए पीएफसी एकमात्र वित्तपोषक होगा और ऋण चुकाने की अवधि 19 वर्ष होगी। परियोजना के अगले वर्ष चालू होने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के साथ 25 वर्ष की अवधि का बिजली खरीद समझौता (पीपीए) 4.33 रुपए प्रति यूनिट के शुल्क पर किया गया है।

एफसीआई ने कंपनियों को कीमत पर बेचा चावल

नईदिल्ली। देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) को लेकर जारी बहस के बीच सरकार ने राज्यसभा में खुलासा किया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों को अपनी खरीद लागत से काफी कम कीमत पर चावल उपलब्ध कराया। सरकार के मुताबिक यह बिक्री ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) के तहत तय दरों पर की गई और इसे किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं माना गया है। सरकार ने बताया कि जून 2025 से जून 2026 के बीच एथेनॉल कंपनियों को 2,250 से 2,320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चावल बेचा गया। वहीं, इसी अवधि में एफसीआई की औसत खरीद लागत 3,720 से 3,889 रुपए प्रति क्विंटल रही यानी निगम ने अपनी खरीद लागत से करीब 40 प्रतिशत कम कीमत पर चावल उपलब्ध कराया।

भारत के नियामकों पर अंदरूनी कब्जा, बेहतर शासन व्यवस्था की जरूरत

के पी कृष्णन

वर्ष 1991 के बाद आर्थिक नीति की रणनीति ने राज्य और बाजार के बीच रिश्ते को नया रूप देने का प्रयास किया। केंद्रीय नियोजन, राज्य के नियंत्रण और अक्सर राज्य के स्वामित्व से हम उस दिशा में बढ़े हैं, जहां उत्पादन में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी है और राज्य की नियामकीय भूमिका है। इस बदलाव के कारण नए संस्थागत ढांचे का निर्माण जरूरी हो गया है, जिसका नाम है सांविधिक नियामकीय प्राधिकरण (एसआरए)।

एसआरए पूरे भारत में फैल गए हैं। केंद्रीय स्तर पर 20 एसआरए हैं और राज्य स्तर पर इससे भी ज्यादा। बिजली वितरण, अचल संपत्ति विकास और जल शुल्क जैसे मामले ये ही देखते हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से में ये नजर आते हैं। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने और बीमा कंपनियों की सॉल्वेंसी पर नजर रखने से लेकर खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के शुल्क तय करने तक इनकी गतिविधियां असंख्य आर्थिक कारकों के रोजमर्रा के कामकाज और व्यवहार्यता पर असर डालती हैं। अब राज्य की काफी शक्ति एसआरए के माध्यम से इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए एसआरए के भीतर अच्छी आंतरिक शासन व्यवस्था भारत की आर्थिक सफलता की बुनियाद होगी।

पारंपरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की शक्तियां तीन शाखाओं (विधायी, न्यायिक और कार्यकारी) में विभाजित होती हैं ताकि किसी एक पर बहुत अधिक शक्ति न हो। किंतु एसआरए के पास एक ही संस्थागत सीमा के भीतर असाधारण और केंद्रित शक्तियां हैं। बाजारों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उनके पास कार्यकारी



शक्तियां होती हैं। आम तौर पर उनके पास कानून बनाने के व्यापक अधिकार भी होते हैं और कुछ मामलों में विवादों का निपटारा करने और दंड लगाने की अर्द्धन्यायिक शक्तियां भी उनके पास होती हैं। संविधान की मौलिक अवधारणाओं से ऐसा विचलन हो तो एसआरए के भीतर अच्छी आंतरिक शासन व्यवस्था भी होनी ही चाहिए।

अर्द्धविधायी शक्ति का आशय आचरण के ऐसे बाध्यकारी नियम लिखने से है, जो आर्थिक एजेंटों की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करते हैं। जब कोई निर्वाचित विधायिका कानून बनाती है तो उस पर राजनीतिक बहस होती है, बहुदलीय समीक्षा होती है, स्थायी समिति उसकी पड़ताल करती है और सार्वजनिक जवाबदेही भी होती है। लेकिन जब कोई एसआरए नियम बनाता है तो वह विधायी शक्ति का प्रयोग करता है किंतु उसकी राजनीतिक जांचपरख नहीं होती। जब अधिकारी इन प्रक्रियाओं के बिना कानून लिखते हैं तो 'लोकतांत्रिक घाटा' होता है। लोकतांत्रिक वैधता बहाल करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि जांचपरख हो एवं जनता को निर्णय प्रक्रिया में फिर शामिल किया जा सके।

किसी एसआरए का बोर्ड महत्त्वपूर्ण निगरानी तंत्र बन सकता है, जो एसआरए के विधायी और कार्यकारी कार्यों में शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण रखे। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र की तेजी से बदलती जटिलताओं से निपटने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए। साथ ही बेहतर लोकतांत्रिक वैधता हासिल करने के लिए समाज से व्यक्तियों को भी शामिल करना जरूरी है। सभी भारतीय एसआरए में आंतरिक सदस्य और बाहरी अंशकालिक सदस्य होते हैं।

इस मामले में आज हम कहां हैं? वित्तीय क्षेत्र के एसआरए पर विचार करें। सभी का नेतृत्व पूर्व अफसरशाह करते हैं। सभी के बोर्ड में पद खाली बने रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 11 सदस्य हैं। इनमें से 2 शैक्षणिक शोधकर्ता हैं और एक बाहरी विशेषज्ञ है। बाकी आठ पूर्व या वर्तमान अफसरशाह, रिजर्व बैंक के अंदरूनी सदस्य या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नौ में से छह सदस्य पूर्व या वर्तमान अफसरशाह हैं, रिजर्व बैंक/सेबी के अंदरूनी सदस्य हैं और एक बाजार विशेषज्ञ है।

उप मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ

धरती का श्रृंगार हैं वृक्षः अरुण साव

रायपुर। वृक्ष धरती का श्रृंगार ही नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज गुरु पूर्णिमा एवं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वन महोत्सव में ये बातें कही। उन्होंने इस अवसर पर ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत पौधरोपण किया। श्री साव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने वन विभाग के ''पौधा तुंहर दुवार'' वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण भी किया।



उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिक्षा के मंदिर में वृक्षारोपण होना अत्यंत सुखद एवं प्रेरणादायी है। गुरु त्याग, समर्पण और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। आज का दिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है, जो हमें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मानव शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए वृक्ष अत्यंत आवश्यक हैं। जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और धरती को जीवनदायी बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पौधरोपण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का दायित्व भी निभाना चाहिए। विधायक दिलीप लहरिया, महापौर पूजा विधानी, बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, बिल्हा जनपद पंचायत के अध्यक्ष रामकुमार कौशिक, कुलपति डॉ. विरेन्द्र कुमार सारस्वत, कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, वनमंडलाधिकारी नीरज कुमार, मोहित जायसवाल और श्री राजेश सिंह ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे। वृक्ष धरती का श्रृंगार ही नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज गुरु पूर्णिमा एवं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वन महोत्सव में ये बातें कही। उन्होंने इस अवसर पर ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत पौधरोपण किया। श्री साव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने वन विभाग के ''पौधा तुंहर दुवार'' वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण भी किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिक्षा के मंदिर में वृक्षारोपण होना अत्यंत सुखद एवं प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री ने अघोर गुरु पीठ बनोरा में किया गुरु दर्शन



रायपुर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ पहुंचकर अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन किए। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए पूजा-अर्चना की तथा पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी से आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुरु भारतीय संस्कृति के ज्ञान, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों के सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं।

खाद के संकट से प्रदेश में हाहाकार सरकार मौन है : दीपक बैज

रायपुर। पूरे प्रदेश में खाद की कमी के कारण बोनी और थरहा का काम प्रभावित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि खाद के संकट से प्रदेश में हाहाकार, सरकार मौन है। किसानी पिछड़ रही है लेकिन सत्ता में बैठे जिम्मेदार केवल फर्जी दावें करके अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। खाद की पर्याप्त उपलब्धता के सरकारी दावों को किसानों के साथ भद्दा मज़ाक है। किसान लगातार आंदोलित हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है लेकिन किसान विरोधी यह सरकार केवल फर्जी दावें करके इस समस्या से ही इनकार कर रही है। इस खरीफ सीजन की खेती का समय तेजी से निकल रहा है लेकिन अभी तक पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम है इसी वजह से खाद और बीज के कालाबाजारी



हो रही है, नकली खाद अमानक गुणवत्ताहीन खाद बिक रहे हैं, किसान महंगे रेट पर खाद बीज खरीदने को मजबूर हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जब सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज उपलब्ध नहीं है तो फिर महंगे दाम पर निजी दुकानों में कैसे बिक रहा है? नकली खाद और बीज आ कहां से रहे हैं? किसानों की शिकायत पर तत्काल ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है ?प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि मात्र 24 हजार टन डीएपी के कागजी आबंटन को अपनी उपलब्धि बता कर श्रेय लेने वाले भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए खुद के ही द्वारा तय लक्ष्य 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन में से केवल 7 लाख 27 हजार 833 मीट्रिक टन खाद ही किसानों को दिया गया है जो कि मांग के आधे से भी कम है। सबसे कम वितरण डीएपी और यूरिया का है जो किसानों के मांग की तुलना में चौथाई भी नहीं है। कभी किस्तों में खाद तो कभी टोकन पर देने के तुगलकी फरमान जारी किए, पिछले साल की तुलना में डीएपी में 40 प्रतिशत कटौती और यूरिया 20 प्रतिशत कम देने का आदेश? फिर टोकन सिस्टम वापस ले लिए, तय लक्ष्य का अब तक आधा भी दिए नहीं फिर यह आबंटन अतिरिक्त कैसे? किसानों को ठगना बंद कर समस्या के समाधान पर ध्यान दे सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि किसान अपने हक और हित की मांग को लेकर इस गूंगी बहरी सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं।

शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कौशल परीक्षा अगस्त में होगी आयोजित

रायपुर। शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा अगस्त 2026 में विभिन्न तिथियों पर मुद्रलेखन एवं कम्प्यूटर मुद्रलेखन कौशल परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभागों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

परीक्षा कार्यक्रम एवं तिथियाँ

01 अगस्त 2026 को अंग्रेजी मुद्रलेखन (गति 10,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा) की परीक्षा 05 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार 02 अगस्त 2026 हिन्दी मुद्रलेखन (गति 10,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा) रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर में चयनित 05 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी।

08 अगस्त 2026 को अंग्रेजी कम्प्यूटर मुद्रलेखन (गति 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा) 08 परीक्षा केंद्रों में, 09 अगस्त 2026 को हिन्दी कम्प्यूटर मुद्रलेखन (गति 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा) 09 परीक्षा केंद्र एवं 16 अगस्त 2026 को बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 01-01 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी।

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश: परीक्षार्थियों को परिषद द्वारा आबंटित परीक्षा केंद्र पर ही निर्धारित बैच एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना परीक्षार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रदेश संयोजक दिनेश सिंह का भव्य स्वागत एवं जन्मदिवस समारोह

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिनेश सिंह जी के रायपुर आगमन पर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ रायपुर संभाग की ओर से उनका पुष्पगुच्छ एवं पुष्पमालाओं से आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात उनके जन्मदिवस के अवसर पर केक काटकर हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में जन्मोत्सव मनाया गया।

इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दिनेश सिंह जी के संगठन के प्रति समर्पण, समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान तथा कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई प्रेषित की। सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना करते हुए संगठन को उनके नेतृत्व में और



अधिक सशक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रदेश सह संयोजक एवं रायपुर संभाग प्रभारी संदीप अग्रवाल जी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी के.एस. नायडू जी, सोशल मीडिया प्रभारी संकल्प दुबे जी, सह प्रभारी हरीश साहू जी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीमती पुष्पा पटेल जी, योगेश शर्मा, स्वतंत्र मिश्रा, रायपुर जिला संयोजक राहुल हरितवाल जी, जिला सह संयोजक सुकृत गणोदवाले, रतीलाल साहू, दीपक तिवारी जी, विशेष आमंत्रित सदस्य अविरल सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में सभी ने दिनेश सिंह के नेतृत्व में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा समाजहित एवं राष्ट्रहित के कार्यों को निरंतर गति देने का संकल्प दोहराया। पूरा कार्यक्रम आत्मीयता, उत्साह एवं संगठनात्मक एकता के वातावरण में संपन्न हुआ।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

एआई के जमाने में विद्यार्थी स्वयं बेहतर भविष्य तय करें : बंसल



रायपुर। स्थानीय महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत एवं उन्हें महाविद्यालयीन जीवन, शैक्षणिक वातावरण और संस्थान की गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीक्षारम्भ-2026 कार्यक्रम का आयोजन उत्साह एवं गरिमापूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजत बंसल, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर, सभापति एवं समाजसेवी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री रजत बंसल ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि महाविद्यालयीन जीवन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य की दिशा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए निरंतर सीखने, समय का सदुपयोग करने तथा समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

हर्षोल्लास से मनाया गया गुरु पूर्णिमा महापर्व

रायपुर। मालवीय रोड स्थित दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में नवोदय तीर्थ वर्षायोग 2026 समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व अत्यंत भक्तिभाव, हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। नवोदय तीर्थ वर्षायोग के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नायक जैन ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रात:काल मंदिर जी स्थित आदिनाथ जिनालय में मूलनायक भगवान आदिनाथ स्वामी का भव्य मस्ताभिषेक संपन्न हुआ। आज प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य बंशी लाल जैन (भोरावत) परिवार को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सर्व जीव हितकारिणी, सुख-शांति व समृद्धि प्रदाता चमत्कारिक शांतिधारा का पावन वाचन किया गया। आज के इस स्वर्णिम अवसर पर शांतिधारा करने का परम सौभाग्य अखिल जैन (मोनू) परिवार को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, पारस बाबा के भक्त (टैगोर नगर) द्वारा आचार्य की संगीतमय पूजन का भव्य आयोजन किया गया। अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल के साथ भक्तों ने नाचते-गाते अत्यंत भक्तिभाव से अर्घ्य समर्पित किए। पूरा भवन आचार्य विद्यासागर महाराज जयकारों से गूंज उठा।मुनि आगम सागर की दिव्य देशना (प्रवचन सार) कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में मुनि आगम सागर ने विशाल धर्मसभा को संबोधित करते हुए गुरु पूर्णिमा के ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला।

वन बंधु परिषद छत्तीसगढ़ इकाई का हैदराबाद में हुआ सम्मान



रायपुर। बन बंधु परिषद छत्तीसगढ़ प्रदेश का विगत दिनों हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में सम्मान किया गया। एकल विद्यालयों के संचालन हेतु सबसे अधिक राशि एकत्र करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर चैप्टर को सम्मानित किया गया। उक्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी कविता राठी व प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता खंडेलवाल ने बताया कि हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम आश्रम में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में संकल्प और विजन पर विचार मंथन किया गया। वन बंधु परिषद द्वारा देशभर में वनवासी क्षेत्रों में पहुंचकर एकल विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में परिषद का विशेष योगदान रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश माहेश्वरी, संरक्षक रमेश सरावगी,रामेश्वर काबरा,रतनी काबरा, राष्ट्रीय सचिव रूपा अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष त्रिभुवन काबरा, संगठन मंत्री शांता सारडा,वेस्ट जोन अध्यक्ष श्याम गर्ग ने छत्तीसगढ़ परिषद के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए भविष्य की रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया।

रक्षाबंधन पर विष्णु भोग चावल की राखियां बनेंगी छत्तीसगढ़ की नई पहचान

रायपुर। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की प्रसिद्ध विष्णु भोग धान और उसके सुगंधित चावल से तैयार की जा रही आकर्षक एवं कलात्मक राखियां इस बार बाजार में विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक बनने वाली ये राखियां केवल स्नेह का बंधन नहीं होंगी, बल्कि आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संकल्प का भी संदेश देंगी। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हस्तकला का अभिनव समन्वय करते हुए विष्णु भोग चावल से आकर्षक राखियां तैयार की हैं। रंग-बिरंगे धागों, पारंपरिक कलात्मक सजावट और सुगंधित विष्णु भोग चावल के संयोजन से निर्मित ये राखियां छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय कृषि उत्पादों की विशिष्टता को देशभर तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगी।इस नवाचार को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राखी निर्माण की आधुनिक एवं आकर्षक तकनीकों के साथ विपणन और गुणवत्ता संबंधी पहलुओं की भी जानकारी दी गई।

रायपुर रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य अभियान का आयोजन



रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के मंडलीय रेलवे चिकित्सालय द्वारा 28 जुलाई 2026 को रेलवे स्टेशन पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद के मार्गदर्शन पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. के.पी.एस. कासीपथी के निर्देशन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी प्रबंधन एवं जीवनरक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करना था। स्वास्थ्य अभियान में कुल 38 रेलवे कर्मचारियों (23 पुरुष एवं 15 महिला) ने भाग लिया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 06 कर्मचारी उच्च रक्तचाप तथा 04 कर्मचारी मधुमेह (डायबिटीज) से प्रभावित पाए गए। इनमें नए एवं पूर्व से ज्ञात दोनों प्रकार के मामलों की पहचान कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं रोगों की रोकथाम संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की सीजी-पीएससी घोटाले को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला

कांग्रेस युवाओं की हितैषी बनने का नाटक कर रही

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी-पीएससी) घोटाले और राज्य में पिछली सरकार के दौरान विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस व पिछली भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बुधवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में श्री श्रीवास ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में सीजी-पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह घोटाला केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं के साथ हुआ एक बड़ा षड्यंत्र था।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास ने कहा



कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण आज देश की दो प्रमुख जाँच एजेंसियाँ सीबीआई व ईडी इस घोटाले की परत-दर-परत जाँच कर रही हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए श्री श्रीवास ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार के समय जब युवाओं ने सबूत दिए थे, तब भी इसे स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी बिलासपुर यात्रा के दौरान ट्रेन से सफर कर रहे थे, तब युवाओं ने उन्हें सीजी-पीएससी घोटाले के प्रमाण दिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने भी तब इस पर चुप्पी साध ली थी! श्री श्रीवास ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस नेता इस घोटाले को स्वीकार करते हैं? यदि उन्हें पश्चाताप है, तो वे प्रदेश के युवाओं से माफी मांगें।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास ने आरोप लगाया कि वन रक्षक परीक्षा की शारीरिक दक्षता दौड़ में ऐसे रिकॉर्ड दिखाए गए जिससे 'उसैन बोल्ट' का विश्व रिकॉर्ड भी टूट जाए, जो कि व्यापक फर्जीवाड़े का उदाहरण है। इसी प्रकार विद्युत नियामक आयोग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर ओएमआर सीट में हेरफेर कर भूपेश बघेल के तत्कालीन ओएसडी के पुत्र का चयन कराया गया, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। अन्य विभागों में हुई भर्तियों का जिक्र करते हुए श्री श्रीवास ने असिस्टेंट प्रोफेसर, वन विभाग के अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक जैसी विभिन्न भर्तियों में भी भाई-भतीजावाद और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए। श्री श्रीवास ने नीट मामले पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस नीट परीक्षा को लेकर युवाओं की हितैषी बनने का पाखण्ड प्रदर्शित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ हुए पीएससी घोटाले और सोनवानी जैसे आरोपियों के बचाव में उनके नेता खड़े दिखाई देते हैं। श्री श्रीवास ने कहा कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार और केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ इस मामले में संलिप्त बड़े-से-बड़े चेहरों और आरोपियों को बख्शेंगी नहीं तथा युवाओं को न्याय दिलाकर रहेंगी।

यात्री सेवा संतुष्टि के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट द्वितीय स्थान तथा विश्व स्तर पर 66वीं रैंक किया प्राप्त

रायपुर। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षण की वर्ष 2026-27 की द्वितीय तिमाही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों में यात्री सेवा संतुष्टि के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर ने द्वितीय स्थान तथा विश्व स्तर पर 66वीं रैंक प्राप्त किया है। इस सर्वेक्षण में रायपुर एयरपोर्ट को 4.93 एएसक्यू रेटिंग प्राप्त हुई, जो एएआई के सभी हवाई अड्डों के औसत 4.88 से अधिक है।

इस सर्वेक्षण में पुणे एयरपोर्ट ने 4.97 एएसक्यू रेटिंग के साथ भारत में प्रथम स्थान एवं विश्व स्तर पर 57वीं रैंक प्राप्त की,



जबकि रायपुर एयरपोर्ट ने 4.93 रेटिंग के साथ भारत में दूसरा स्थान एवं विश्व स्तर पर 66वीं रैंक हासिल की। इसके बाद पटना, वाराणसी, देहरादून, कोलकाता, भुवनेश्वर, गोवा एवं इंदौर एयरपोर्ट क्रमशः अगले स्थानों पर रहे। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कार्यक्रम, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा संचालित विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित यात्री संतुष्टि मूल्यांकन कार्यक्रम है। इसमें यात्रियों से सीधे प्राप्त फीडबैक के आधार पर हवाई अड्डों की स्वच्छता, सुरक्षा, चेक-इन प्रक्रिया, प्रतीक्षा समय, कर्मचारियों के व्यवहार, यात्री सुविधाओं, संकेतक व्यवस्था तथा समग्र यात्रा अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है। इस कारण एएसक्यू रैंकिंग को विश्वभर में हवाई अड्डों की सेवा गुणवत्ता का महत्वपूर्ण मानक माना जाता है।

रायपुर एयरपोर्ट की यह उपलब्धि एयरपोर्ट पर कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, एयरलाइंस, सीआईएसएफ, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों एवं यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता का परिणाम है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.